● वर्ष-4
● अंक-101
रायपुर, शुक्रवार
06 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» अगर आपने ताजमहल नहीं देखाया तो....

महाराष्ट्र में अब देवेंद्र सरकार

एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने उपमुख्यमंत्री

मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के 12वें दिन आखिरकार राज्य में नई सरकार का गठन हुआ और भाजपा नेता और पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे नई सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका में होंगे, जबकि शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के पद में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्होंने एक बार फिर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है।

मोदी, एनडीए के दिग्गज बने साक्षी

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत राजग शासित कई राज्यों के उप-मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा नीत महायुति के हजारों समर्थक शामिल हुए। यह कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के करीब दो हफ्ते बाद आजाद मैदान में आयोजित किया गया।

महायुति की पहली कैबिनेट बैठक

महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद महायुति सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। वहीं इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, इस बार टेस्ट मैच जैसी पारी होगी। हम महाराष्ट्र को हर क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना की धनराशि में बढ़ोतरी की है। सीएम फडणवीस ने एलान करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना में अभी 1500 रुपये दे रहे हैं, इसे बढ़ाकर 2100 रुपये करेंगे। हालांकि इसमें बढ़ोतरी कब से की जाएगी उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन कहा कि, हम आर्थिक स्त्रोत मजबूत करेंगे, फिर इसे बढ़ाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा, राज्य के कैबिनेट में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। जबकि 7, 8 और 9 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा। 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा मंत्रिमंडल तय हो चुका है।

वक्फ संपत्तियों को लेकर समिति सख्त

जगदंबिका पाल बोले- राज्यों से मांगा गया ब्योरा

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने विवादित संपत्तियों को लेकर सख्ती जताई है। गुरुवार को हुई जेपीसी बैठक में तय किया गया कि विवादित संपत्तियों के मामले में राज्यों से ब्योरा मांगा जाए। इसे लेकर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ की विवादित संपत्तियों का ब्योरा मुहैया कराने के लिए राज्यों को पत्र लिखा जा चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो राज्यों के मुख्य सचिवों को समिति के समक्ष पेश होने को कहा जा सकता है।

जेपीसी का कार्यकाल अगले साल बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाए जाने के बाद समिति की पहली बैठक हुई। अध्यक्ष पाल ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने समिति के विभिन्न सदस्यों की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश किए। पाल ने बताया कि ये जवाब 887 पन्नों के हैं। अगले कुछ दिन इनकी जांच की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अगली बैठक 11-12 दिसंबर को होगी। समिति के एक सदस्य ने दावा किया कि मंत्रालयों की तरफ से पेश किए गए जवाब काफी उलझाने वाले हैं। विपक्ष के सदस्यों की तरफ से अगले कुछ दिनों में उन पर स्पष्टीकरण

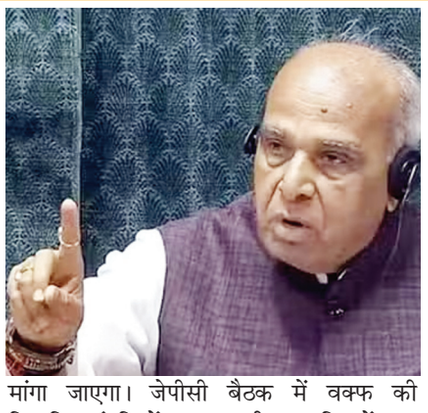

मांगा जाएगा। जेपीसी बैठक में वक्फ की विवादित संपत्तियों का मुद्दा भी उठा, जिसमें हाल ही में राज्य सरकारों को ब्योरा देने के लिए पत्र भेजा जा चुका है।

सच्चर समिति की रिपोर्ट पर मांगी गई जानकारी

पाल ने बताया कि सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में वक्फ की कई संपत्तियों पर राज्य सरकार या उसके विभाग का अनधिकृत कब्जा होने की जानकारी दी थी। राज्यों से इसी पर मौजूदा स्थिति पर अपडेट जानकारी मांगी गई है। सच्चर समिति को 2005-06 में विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों ने बताया था कि दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी विवादित संपत्तियां हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60 और ओडिशा में 53 ऐसी संपत्तियां होने का दावा किया गया था।

क्या है पूरा मामला?

लोकसभा में आठ अगस्त को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने %वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024% पेश किया था। इसके साथ ही इससे जुड़े निष्क्रिय हो चुके पुराने अधिनियम को कागजों से हटाने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024% को भी पेश किया गया था। नए विधेयक का नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम होगा। अंग्रेजी में यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एंपावरमेंट एफिशिएंट एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद। इस विधेयक का विपक्ष ने पुरजोप विरोध किया था। उसके बाद नौ अगस्त को इसे आगे की चर्चा के लिए संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित समिति का कार्यकाल बजट सत्र 2025 के आखिरी दिन तक बढ़ाया गया है। लोकसभा ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी थी।

संभल-बांग्लादेश हिंसा का स्वभाव और डीएनए एक-योगी

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक बार फिर अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से वैश्विक शहर के रूप में नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। याद रखें कि पीएम के प्रयासों से इस साल जनवरी में कैसे नरेंद्र मोदी, भगवान राम पांच सौ साल बाद फिर से मंदिर में विराजमान हुए हैं, जो कोई भी भगवान राम और माता जानकी का सम्मान नहीं करता, चाहे वे आपके कितने भी प्रिय क्यों न हों, उसे दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। इसीलिए राम भक्तों ने 1990 में नारा दिया था, जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। राजनीति में डॉ. राम मनोहर लोहिया आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। आज की राजनीति में सच्चा समाजवादी स्वतंत्र है संपत्ति और बच्चों के प्रति लगाव से हालाँकि, आज के समाजवादी परिवारवादी बन गये हैं। अपराधियों और गुंडों के संरक्षण के बिना उनकी हालत पानी के बिना संघर्ष कर रही मछली की तरह हो जाती है... वे लोहिया के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन उनके एक भी आदर्श को नहीं अपना पाते हैं।

राम कथा पार्क में रामायण मेले के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद कीजिए 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी वही हुआ और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों का स्वभाव और उनका डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, तो वही तत्व यहां भी इस बारे में बात करने वाले ऐसे हैं, जिनके पास विदेश में संपत्ति है भाग जायेंगे और दूसरों को यहां मरने के लिए छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री ने लगे हाथ स्वयं की आस्था का भी इजहार किया। साथ ही कहा कि हमने प्रभु राम को आदर्श माना है और उनके आदर्श से कुछ भी ले सके, तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज जब लोग छोटे-छोटे स्वार्थ के लिए मारने-मरने पर उतारू रहते हैं, तो श्री राम का आदर्श हमारा मार्गदर्शन करता है, पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने क्षण भर की भी देरी किए बिना अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया.

मैं अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयारः अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपने डीएनए की जांच करवाने के लिए तैयार हैं बशर्ते मुख्यमंत्री भी अपने डीएनए की जांच कराएं। योगी ने अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के बाद विपक्षी दलों पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि अयोध्या व संभल में मुगल शासक बाबर की सेना ने जो किया और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है.

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिशकाल में हुए जनजातीय विद्रोह की झांकी को वास्तविक स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। ब्रिटिशकाल के दौर में अपनी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए हुए जनजातीय विद्रोह के दौरान कई छत्तीसगढ़ के अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए।

प्रमुख समाचार

मान मनौवल के बाद तैयार हुए एकनाथ शिंदे

मुंबई। गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस की शपथ से कुछ घंटे पहले, शिंदे खेमे के नेता उदय सामंत ने कहा कि आज एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इससे मपहले उन्होंने कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं तो उनकी पार्टी का कोई भी विधायक नई सरकार में कोई पद स्वीकार नहीं करेगा। सामंत के हवाले से कहा गया कि अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते हैं, तो कोई भी शिवसेना विधायक नई सरकार में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। शिंदे सेना के विधायक उदय सामंत ने कहा कि पार्टी ने शिंदे से उपमुख्यमंत्री पद संभालने का अनुरोध किया है, अगले 30 मिनट के भीतर निर्णय होने की उम्मीद है। सेना नेता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)-सपा के जितेंद्र अवहाद की एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर भी टिप्पणी की और कहा कि दोस्ती पर कोई आचार संहिता नहीं है। सामंत ने कहा कि राजनीति में, इस बारे में कोई आचार संहिता नहीं है कि कौन किसका मित्र है। आव्हाड और शिंदे दोनों ठाणे से हैं और इसीलिए वे दोस्त हैं और साथ रहेंगे।

पुरातत्व स्थलों पर सरकार का जवाब, स्थल गायब नहीं हुआ

नई दिल्ली। इन दिनों देश में धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर हंगामा मचा है। इन सबके बीच गुरुवार को सरकार ने राज्यसभा में पुरातत्व स्थलों को लेकर बड़ी जानकारी साझा की। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि जनवरी 2020 से अक्तूबर 2024 के बीच देश में कोई पुरातत्व स्थल न तो गायब हुआ है और न ही नष्ट हुआ है। राज्यसभा में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 से अक्तूबर 2024 की अवधि के बीच किसी भी स्थल को पुरातत्व स्थलों की सूची से नहीं हटाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 2020 से 2024 के बीच वडक्कुपट्टु और आदिचनल्लूर में खोदाई की थी। उन्होंने कहा कि कांचीपुरम का वडक्कुपट्टु मध्य पुरापाषाण काल से लेकर प्रारंभिक मध्यकाल तक का है। यहां खोदाई के दौरान मध्य पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के पुरावशेष मिले हैं। इसमें तमिल ब्राह्मी में अंकित मूर्तियां, कीमती पत्थर के मोती, तांबे के सिक्के और सोने की कई चीजें शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि

बैंक नोटों से मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की तैयारी

ढ़ाका। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के करीब चार महीने बाद, बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान - उनके पिता और देश की स्थापना के पीछे के प्रतिष्ठित व्यक्ति - की छवि को अपने करेंसी नोटों से मिटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बांग्लादेश बैंक नए नोट छाप रहा है, जिनमें जुलाई विद्रोह की तस्वीरें शामिल हैं, एक स्थानीय समाचार पत्र ने गुरुवार को बताया कि छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए, जिसके कारण 5 अगस्त को शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था। जिसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख, मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्रीय बैंक के अनुसार, अंतरिम सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1,000 टका के बैंक नोट छापे जा रहे हैं। अखबार ने बैंक के हवाले से बताया, %नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं और जुलाई के विद्रोह के दौरान बनाई गई भित्तिचित्र को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी में पंजाब-हरियाणा के किसान

नई दिल्ली। पंजाब के किसान 6 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रस्तावित मार्च की तैयारी में हैं।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बताया कि वे सिंघू सीमा पर उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि कल दोपहर एक बजे जत्था यहां से (दिल्ली के लिए) रवाना होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार अच्छा संदेश देगी और हमें नहीं रोकेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है, ऐसा लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बन गई है। किसान नेता ने आगे कहा कि हरियाणा के कई किसान नेताओं के घरों पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। हम केंद्र सरकार को यह कहने का मौका नहीं देंगे कि किसान अहंकारी हैं और बात नहीं करना चाहते। जब भी हमें बातचीत का निमंत्रण मिलेगा हम इस पर फैसला करेंगे। हालांकि, फिलहाल सीमा पर सुरक्षा अधिकारियों की कोई अतिरिक्त तैनाती नहीं की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने राष्ट्रीय राजधानी की ओर किसानों के मार्च से पहले दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग पर सिंघू सीमा पर एक महत्वपूर्ण तैनाती की योजना बनाई है।

हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का टूटा घमंड

नई दिल्ली। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में ही होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) इस नतीजे पर पहुंच गया है कि टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में ही किया जाएगा। वहीं, भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। इसकी जानकारी गुरुवार को आईसीसी के एक शीर्ष सूत्र ने पीटीआई को दी। उन्होंने कहा- गुरुवार को दुबई में अपने मुख्यालय में नए अध्यक्ष जय शाह और पाकिस्तान सहित निदेशक मंडल के बीच एक अनौपचारिक बैठक के दौरान निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। सभी पक्षों ने सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी यूएई और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। यह सभी हितधारकों के लिए जीत की स्थिति है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएगी। पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह आईसीसी की बैठक में बहिष्कार की धमकी वापस लेते हुए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई थी और 2031 तक अपने लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की मांग की थी। हालांकि, आईसीसी ने 2027 तक अपने सभी टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई है। इस दौरान भारत अगले साल अक्तूबर में महिला वनडे विश्व कप और श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से 2026 पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा।

निशिकांत दुबे के बयान पर लोकसभा में हंगामा, सांसदों को ओम बिरला की सलाह

संसद के शीतकालीन सत्र का आज नौवा दिन था। नवें दिन लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। निशिकांत दुबे के एक बयान को लेकर विपक्ष भड़क गया। वहीं राज्यसभा में कुछ काम का जरूर हुआ। लेकिन विपक्ष का हंगामा भी समय-समय पर जारी रहा। वहीं, भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि छह हवाई अड्डों को गहन, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अदाणी समूह को पट्टे पर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदस्यों से नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करने और सदन में बिल्ले आदि लगाकर नहीं आने का आग्रह किया।

लोकसभा की कार्यवाही

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों पर विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर कुछ ही मिनट के अंदर दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछने के लिए कुछ सवाल उठाए जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच सदन की बैठक दोपहर करीब 12 बजकर 10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही दो बजे फिर से आरंभ होने पर कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। उनकी मांग थी कि लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई को बोलने का मौका दिया जाए। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि रेल

संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा हो चुकी है और विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव को जवाब देना है, ऐसे में विपक्षी सदस्य सदन चलने दें।

पाल ने कहा, ''कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया था कि चर्चा के लिए रेल का विधेयक लेंगे। इस पर हुई चर्चा में सदस्यों ने भागीदारी की। अब माननीय मंत्री का जवाब सुनना है।'' उन्होंने गौरव गोगोई से कहा, ''शून्य प्रहर में निशिकांत दुबे जी को अवसर मिला, आपको भी अवसर मिला...आपको लगता है कि कोई विषय है तो उस पर अध्यक्ष जी को निर्णय करना है।'' संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सदन में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों का व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कहा, ''कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोगों ने हर विधेयक पर समय तय किया था। अब हंगामा कर रहे हैं...यहां तय किया गया था कि तख्तियां लेकर सदन में नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर फैशन शो किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं।'' रीजीजू ने कहा, ''इस तरह से हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। हंगामा करने से वोट नहीं मिलता है। चर्चा करने से लोग पसंद करेंगे।'' हंगामे के बीच ही, पाल ने रेल मंत्री वैष्णव का नाम बुधवार को हुई चर्चा परजवाब देने के लिए पुकारा। वैष्णव ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी तेज कर दी।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों में एक साल के भीतर 1.68 लाख लोगों की मौत हुई और मरने वालों में 60 प्रतिशत युवा थे। उन्होंने सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह स्थिति दुखद है और इसे रोकने के लिए समाज को भी सहयोग करना होगा।

राज्यसभा की कार्यवाही

ग्रामीण समुदायों, खास कर महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए डाक घरों को महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि इनका का आधुनिकीकरण किया गया है ताकि सेवाओं में कोई कमी न रहे और यही वजह है कि गांवों में स्वसहायता समूहों के लिए ये डाक घर निर्यात केंद्रों की भूमिका निभा रहे हैं। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेन्नासानी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि डाक घर आज भी प्रासंगिक हैं।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम किसी भी अन्य स्थान पर सबसे बड़े लोकतंत्र को गहरे राज्य द्वारा निष्क्रिय बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। इस सदन को हमारी संप्रभुता के लिए हानिकारक और खतरनाक किसी भी प्रवृत्ति, किसी भी पहल को बेअसर करने के लिए एकजुट होना चाहिए। मैं समय दूंगा। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और हमें सभी से राय लेने की जरूरत है। वहीं, सुधांशु त्रिवेदी इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओसीसीआरपी भारत में झूठी बातें फैलाता है।

बीजापुर में 2 पूर्व सरपंच की अपहरण के बाद हत्या, मिले नक्सली पर्चे

बीजापुर। जिले में एक दिन में नक्सलियों ने भाजपा से जुड़े दो पूर्व सरपंचों की धारदार हथियारों से नक्सलियों ने हत्या कर दी है। नक्सलियों ने आज भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के सुकलु फरसा और कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलम को मौत के घाट उतार दिया है। नक्सलियों ने दोनों सरपंचों को अगल-अलग स्थान से अपरहण किया था, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं पर्चे के माध्यम से नक्सलियों ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी छोडने की चेतावनी दी है। बीजापुर एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्ना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है, जो भी आगे की प्रक्रिया होगी पूरा करेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बिरयाभूमि गांव के रास्ते से पूर्व सरपंच सुकलु फरसा का अपहरण कर लिया था। वहीं नैमेड थाना क्षेत्र कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम अवलम को नक्सलियों ने मुर्गा बाजार से अगवा किया था और अब दोनों की हत्या कर दी गई है। नक्सलियों ने पूर्व सरपंच सुकलु फरसा के शव पर प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें नक्सलियों ने उस पर भाजपा से जुडने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही लिखा है कि तीन बार उन्होने पूर्व सरपंच को भाजपा पार्टी से दूरी बनाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानने पर चौथी बार में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी है। पूर्व सरपंच के अपहरण के बाद बुधवार को सुकलु फरसा के परिजन और बेटी यामिनी फरसा ने थाना में सूचना देने के दौरान सोशल मीडिया में पिता को छोडने की मार्मिक अपील भी की थी, लेकिन नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। जांगला थाना एवं थाना नैमेड़ पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही कर रही है।

अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में डीआरजी का जवान बिरेंद्र सोरी शहीद

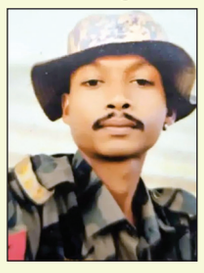

नारायणपुर। अबूझमाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में एक डीआरजी का जवान प्रधान आरक्षक बिरेंद्र कुमार सोरी शहीद हो गया है। वहीं कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। शहीद जवान के शव को लेकर पुलिस की एक टीम नारायणपुर पहुंच गई है, दूसरी टीम अभी जंगल में ही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सोनपुर और कोहकामेटा बॉर्डर के पास जंगल में बीएसएफ और डीआरजी का संयुक्त बल नक्सलियों के एंबुश में फंस गया था।

बुधवार दोपहर 1 बजे से दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान नारायणपुर में प्रधान आरक्षक बिरेंद्र कुमार सोरी उम्र 36वर्ष को गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही शहादत हो गई। अबूझमाड़ में नक्सली पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की वर्षगांठ मना रहे थे, इनके बड़े कैडर्स के नक्सली भी वहां मौजूद थे। इसी सूचना के आधार पर जवानों को अभियान पर रवाना किया गया था। बीरेंद्र कुमार सोरी 2010 में नारायणपुर जिला बल में आरक्षक के पद पर भर्ती हुए थे। 2018 में नक्सल ऑपरेशन में वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, वे कांकेर के नरहरपुर के रहने वाले थे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विस्तृत जानकारी अभियान पूरा होने के बाद पृथक से जारी की जावेगी।

पुलिस व नक्सलियों के चलते आदिवासियों के जीवन शैली पर विपरीत असर पड़ रहा : ठाकुर

जगदलपुर। पुलिस और नक्सलियों के चलते आदिवासियों के दैनिक जीवन शैली पर विपरीत असर पड़ रहा है। जहां एक ओर नक्सल उन्मूलन के नाम पर बेगुनाह आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर मारा जा रहा और जेलों में भेजा जा रहा है। वहीं बस्तर संभाग में करीब ढाई दशक से अंचल में शोषण और उत्पीडन के खिलाफ खड़े होने का दावा करने वाले नक्सलियों के चलते आदिवासियों के जीवन शैली पर असर पड़ रहा है। जिसकी सर्व आदिवासी समाज निंदा करता है।

सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि नक्सली संगठन द्वारा दीगर राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाना आदिवासी समाज के द्वंदात्मक बौद्धिक, राजनीतिक विकास में बाधा डालने जैसा कृत्य है। लगातार हो रही हत्याओं से आदिवासी समाज क्षुब्द है, और ऐसी घटनाओं की निंदा करता है। प्रकाश ठाकुर ने कहा कि आदिवासियों की हत्या से कोई क्रांति कैसे आ सकती है? मुखबिरी के नाम पर, गरीबों के शोषण और अत्याचार में शामिल होने का आरोप लगाकर आदिवासियों की हत्या की जा रही है। अब किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े होने का आरोप लगा कर आदिवासियों के खात्मे के दिशा में नक्सलियों की साजिश सामने आ रही है जो निंदनीय है।

ईंटा बनाने के व्यवसाय में सहायक सिद्ध हो रहा महतारी वंदन की राशि

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही विकासखण्ड के ग्राम धरहर की श्रीमती बिंदिया बाई प्रजापति पूरे परिवार के साथ मिलकर ईंटा बनाने के पैतृक व्यवसाय से जीवनयापन करती है। उन्हें जबसे महतारी वंदन योजना के तहत हर महिने एक-एक हजार रूपए मिल रहा है, उनके चेहरे में खुशी की चमक आई है। बिंदिया बाई महतारी वंदन की राशि का उपयोग अपने ईंट व्यवसाय के कारोबार को बढ़ाने में कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर बिंदिया बाई को पहले ईंट बनाने के लिए मिट्टी, पकाने के लिए भूंसी-लकड़ी आदि के लिए उधारी लेना पड़ता था, अब उन्हें दूसरों के सामने हाथ फेलाना नहीं पड़ता। बिंदिया बाई को मार्च 2024 से हर महिने हजार रूपए मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार जताया है। बिंदिया बाई ने बताया कि महतारी वंदन की राशि मिल रहा है, तब से मेरे परिवार में खुशहाली आया है। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने पर दोहरी खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

राख की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, वाहनों की लगी लंबी कतार

कोरबा। कोरबा में राखड़ के परिवहन के कारण आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। नियमों को ताकर पर रखकर भारी वाहनों में राखड़ का परिवहन किया जा रहा है,जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ओव्हरलोड वाहनों से गिरने वाली राख के कारण लोग काफी परेशान है यही वजह है,कि नकटीखार गांव में रहने वाले लोगों ने कोरबा-उरगा बायपास मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन से मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है।

समय के साथ ही कोरबा जिले में राखड़ की समस्या काफी विकराल हो गई है। पॉवर प्लांट से निकलने वाली राख की उपयोगिता शत् प्रतिशत साबित नहीं होने के कारण ये अब लोगों के जी का जंजाल बन गया है। भारी वाहनों के माध्यम से राखड़ का परिवहन किया जा रहा है,जिसे कहीं भी फेंक दिया जाता है जिसके बुरे परिणाम सामने आ रहे है। ओव्हरलोड वाहनों से गिरने वाली राख ने नकटीखार गांव में रहने वाले लोगों का जीना हराम कर रखा है। राख के कारण प्रदूषण का दायरा काफी बढ़ गया है यही वजह है,कि लोगों ने परेशान होकर कोरबा-उरगा बायपास मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन से मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों का आरोप है,कि राख की समस्या का समाधान करने को लेकर जिला प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रही।

नकटीखार की सरपंच रूपा तिर्की ने बताया राखड़ परिवहन के चलते कई गांव के लोग काफी परेशान हैं कई लोगों की जान चली गई है वहीं कई लोग घायल हो गए हैं पानी छिड़काव और ओवरलोड राखड़ परिवहन को लेकर जिला प्रशासन को अवगत करा जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का प्रबंध नहीं लग रहा है जिसके चलते उन्हें आज चक्का जाम करना पड़ा।

जनप्रतिनिधि अजीत दास महंत ने बताया कि कल रात 8:00 बजे से सभी ग्रामीण सड़क पर आग जला कर बैठे हुए हैं कई बार आंदोलन और प्रदर्शन किया जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है मजबूरन आज उन्हें सड़क पर आना पड़ा और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

पंचायत की सरपंच के नेतृत्व में चक्काजाम प्रदर्शन चल रहा है। मार्ग पर लाम लगने के कारण वाहन के पहिए जहां तहां थम गए है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी लोगों से बात करने मौके पर नहीं पहुंचा है। गांव के ग्रामीण आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। उन्होंने स्पष्ट रुप से कह दिया है,कि समस्या का स्थाई समाधान मिलने पर ही प्रदर्शन को समाप्त किया जाएगा।

बस्तर जिले के राष्ट्रीय स्तर की परख परीक्षा में शामिल हुए 2808 छात्र-छात्राएं

जगदलपुर। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण हेतु निर्धारित राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण परीक्षा परख का आयोजन 5 दिसम्बर को जिले के 114 शालाओं में सम्पन्न हुई। जिले के 114 शालाओं में आयोजित परख परीक्षा में सैंपलिंग हेतु कुल 2808 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। विदित हो कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली परख परीक्षा का उद्देश्य मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाते हुए देश के विभिन्न बोर्डों में एक जैसी मूल्यांकन तकनीक लाने के साथ यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक मंच पर लाने का काम करेगा। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई है जो मुख्यतः बड़े पैमाने पर मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन और परीक्षा सुधार जैसे तीन प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करेगी।

परख परीक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जिले से स्तर 3, 6, और 9 के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निजी शालाएं एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कुल 114 शालाओं का चयन किया गया था। तीनों स्तर के लिए राज्य सरकार की 49, केंद्र सरकार की 5, निजी क्षेत्र की 43 और अनुदान प्राप्त 17 शालाओं का चयन हुआ था जिसमें हिंदी माध्यम की 77 एवं अंग्रेजी माध्यम की 37 शालाएं हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल एवं जिला मिशन समन्वयक अखिलेश मिश्र द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के 114 शालाओं में आयोजित परख परीक्षा में सैंपलिंग हेतु कुल 2808 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। जिनका चयन प्रत्येक शाला में डाइट द्वारा नियुक्त फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया। उन्होंने साथ में यह भी जानकारी दी है कि प्रत्येक शाला में डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर सीबीएसई द्वारा आब्जर्वर भी नियुक्त किये गए थे ताकि जिले के 114 शालाओं में निर्विघ्न रूप से परीक्षा सम्पन्न हो सके। जिला प्रशासन की ओर से परख परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को दी गई थी। उक्त परीक्षा में 95 प्रतिशत विद्यार्थियों के उपस्थित होने की जानकारी ब्लाकों से प्राप्त हुई है।

एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र टॉयलेट में रहने-पढ़ने को मजबूर

नारायणपुर। एकलव्य आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों को टॉयेलट में रहना और पढ़ना पड़ रहा है। इस अमानवीय हालात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में प्रदेश सरकार में मंत्री केदार कश्यप का अजीबो-गरीब बयान सामने आया है, जिसमें वे व्यवस्था सुधारने की बजाए वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आज हम एक ऐसी खबर बता रहे हैं, जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। वाकया छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के छोटे डोंगर स्थित आवासीय विद्यालय का है, जहां कमरों की कमी के कारण बच्चों को टॉयलेट में रहना-पढ़ना पड़ रहा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। बालिकाओं को टॉयलेट और स्नानगृह की कमी के साथ-साथ सुरक्षा का भी डर सताता है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब आपको पता चले कि स्नानगृह में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हॉस्टल के वार्डन अंकित सिंह बताते हैं कि हॉस्टल में कमरे नहीं हैं। बच्चों को टॉयलेट में रहना पड़ रहा है हमने कई बार अधिकारियों को शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बच्चों के रहने के लिए न तो कमरे हैं, न ही बिस्तर। मजबूरी में टॉयलेट में ठिकाना बनाना पड़ा। यह बेहद शर्मनाक है कि बच्चों की ये दयनीय स्थिति किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजरों से नहीं बची, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं इस मुद्दे पर नारायणपुर विधायक और वन मंत्री केदार कश्यप ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए व्यवस्था सुधारने की बजाए पहले वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जिसके बाद व्यवस्था को संभालने वालों पर ध्यान दिया जाएगा। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जब भालू से भिड़ बैठा युवक लहूलुहान हालत में पहुंचा घर

जगदलपुर। जगदलपुर के नगरनार थाना क्षेत्र के ग्राम उलनार में रहने वाला ग्रामीण अपने घर से कुछ दूरी स्थित खेत से तार निकालने के लिए गया हुआ था, जहां एक भालू ने उसके ऊपर हमला कर दिया। किसी तरह ग्रामीण ने भालू से अपनी जान को बचाते हुए घर पहुंचा, जिसे बेहतर उपचार के लिए मेकाज लाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण के परिजनों ने बताया कि उलनार माझिपारा निवासी जगबंधु बघेल पिता चैतू बघेल (30) अपने घर से 3 किमी दूर खेत में लगे तार को निकाल रहा था कि अचानक से जंगल में एक भालू ने बुधवार की दोपहर को उसके ऊपर हमला कर दिया। अचानक से भालू के हमले से ग्रामीण कुछ समझ पाता इससे पहले ही भालू ने ग्रामीण के हाथ को पकड़ लिया। ग्रामीण ने हिम्मत नहीं खोई और भालू से लड़ पड़ा, करीब 20 मिनट की लड़ाई के बाद भालू भाग गया, ग्रामीण घायल अवस्था मे होने के बाद भी अपने घर पहुंचा, जहां परिजनों को मामले की जानकरी दी। जिसके बाद परिजनों ने ग्रामीण को बेहतर उपचार के लिए मेकाज में भर्ती किया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है।

मामूली बात पर बालोद में चला चाकू, एक शख्स घायल

बालोद। बालोद सीटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जहां मामूली सी बात पर चाकू से हमला किया गया है। बच्चों के बीच हुए विवाद चाकूबाजी तक पहुंच गया। घटना में संन्तोष योगी नामक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज जारी है। मामले को लेकर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। चाकूबाजी की घटना से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूरे मामले में सिटी कोतवाली के इंचार्ज रवि शंकर पांडे ने बताया कि घटना बीती रात को घटित हुई है और बालोद शहर के मस्जिद के पास की घटना है। जिसमें घायल व्यक्ति को अस्पताल लाया गया जहां उसका इलाज किया गया है। आरोपी नाबालिग है, उसकी तलाश की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात में दो पक्षों में विवाद चल रहा था। जहां पर बालोद शहर के नयापारा निवासी संतोष योगी ने बीच-बचाव किया। जिसके बाद नाबालिग युवक ने चाकू से हमला कर दिया।

मॉर्निंग वॉक पर निकले दो युवकों पर चाकू से हमला

कांकेर। कांकेर में मॉर्निंग वॉक पर निकले नाबालिग समेत दो युवकों पर चाकू से हमला किये जाने की घटना सामने आई है। बाइक पर लूट के इरादे से आये तीन अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पूरी घटना चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम रतेसरा और कोचवाही की बताई जा रही है। घायल युवक योगेश्वर कांगे ने बताया कि वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था। इसी दौरान बाइक सवार तीन नकबपोश युवक पहुंचे और पेट्रोल पंप का पता पूछने लगे। पता बताने के बाद आरोपियों ने पैसे और मोबाइल देने की मांग की। मना करने पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने एक 17 वर्षीय नाबालिक युवक पर चाकू से हमला कर दो मोबाइल लूट कर ले गए। नेशनल हाइवे में इस तरह की वारदात के सामने आने से लोगों मे दहशत का माहौल है। वहीं घायल युवकों का उपचार जारी है। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है।

आपसी विवाद में हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार

कोंड़ागांव। थाना उरन्दाबेड़ा पुलिस ने हत्या के आरोपी सगाराम मण्डावी पिता सनाऊराम मण्डावी उम्र 45 वर्ष ग्राम कुलानार को थाना उरन्दाबेड़ा के अपराध क्रमाक 12/2024 धारा 103(1) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर आज गुरूवार को कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि 3 दिसंबर 2024 के रात्रि 09.30 बजे लगभग इसके मां सगनी बाई नेताम पड़ोसी सगाराम मण्डावी के घर धान मिजाई पश्चात् पार्टी मनाने गयी थी। देर रात तक अपने घर वापस नहीं लौटी तब इसका पति मंशाराम नेताम इसे लेने सगाराम मण्डावी के घर गया जहां आंगन में इसके पत्नी एवं आरोपी शराब पी रहे थे। जिसे डाटने एवं गाली देने से नाराज होकर आक्रोश में आकर आरोपी सगाराम मण्डावी द्वारा मंशाराम नेताम को धक्का देकर जमीन में गिराकर लात, हाथ मुक्का से पेट पीठ एवं पसली को मारपीट किया गया। इस दौरान बीच बचाव प्रार्थिया द्वारा किया गया। मारपीट से अत्यधिक जख्मी होकर मंशाराम बेहोश हो गया।

बीएमओ की मनमानी से तंग आकर डॉक्टरों ने खोला मोर्चा

गरियाबंद। फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा विशेषज्ञों ने लामबंद होकर खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. वीरेंद्र हेरोदिया की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जिला चिकित्सा अधिकारी गरियाबंद और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी की गई थी। शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज चिकित्सा अधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। वहीं इस संबंध में डॉक्टरों ने आज राजिम विधायक रोहित साहू से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया और लिखित शिकायत सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

टीका लगने के बाद नवजात के पैर में हुआ गंभीर इंफेक्शन

मुंगेली। बेबस मां-पिता ने जिला प्रशासन और जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन से अपने नवजात बच्चे को लेकर गुहार लगाई है। माता-पिता का आरोप है कि उनके नवजात शिशु को नर्स ने फोन पर बात करते हुए लापरवाही से टीका लगाया है, जिससे इस कदर इन्फेक्शन हुआ कि अब डॉक्टर पैर काटने की बात कह रहे हैं।

मामला मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम भठलीकला है। जहां रोजी-मजदूरी करने वाले निमेष साहू की पत्नी पंच कुमारी अपने नवजात बच्चे को टीका लगाने के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई थी। माता-पिता का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स रीना ग्वाल ने फोन से बात करते हुए बच्चे को लापरवाही पूर्वक टीका लगाया। टीका लगाने के कुछ ही देर बाद बच्चे के पैर में सूजन होने लगा।

बहुत ज्यादा सूजन की वजह से दूसरे दिन फिर बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉ निधि तिवारी ने सिकाई करने को कहकर उन्हें फिर लौटा दिए।

बुजुर्ग महिला का तेंदुआ ने किया शिकार, घर से घसीटकर ले गया जंगल

धमतरी। धमतरी जिले के मगरलोड में तेंदुआ एक बुजुर्ग महिला को जंगल के अंदर उठाकर ले गया।इसके बाद उसका शिकार कर लिया। बुजुर्ग महिला का शव क्षत विक्षत हालत में जंगल के अंदर मिला है।आपको बता दें कि जंगली जानवर के हमले से ये जिले में दूसरी मौत है।

बताया जा रहा है कि महिला घर में बिना दरवाजे के मकान में सो रही थी। तभी रात में तेंदुआ पहुंचा और महिला को घसीटते हुए ले गया। बता दें कि एक दिन पहले एक हाथी के बच्चे ने नगरी क्षेत्र में घर अंदर से एक 4 वर्षीय बच्ची को पटक कर मार डाला था। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

डीएफओ कृष्ण जाधव ने बताया मगरलोड इलाके के उत्तर सिंगपुर रेंज अंतर्गत ग्राम मड़ेली में बुजुर्ग सुखवती कमार घर मे सो रही थी रात में तेंदुए ने बुजुर्ग महिला को घर से ले जाकर जंगल मे ले गया। महिला की लाश जंगल मे क्षत विक्षत हालत में मिली है। मृतिका के परिजनों को 6 लाख की आर्थिक मदद जल्द दी जाएगी।

गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मगरलोड में बुजुर्ग महिला को तेंदुआ घर से घसीटकर जंगल में ले गया।इसके बाद उसे मारकर खा गया। बुजुर्ग महिला सुखवती कमार घर में अकेली सोई हुई थी। घर में दरवाजा नहीं होने की वजह से तेंदुआ अंदर घुस गया और सुखवती कमार को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। तेंदुए ने महिला के शरीर के आधे हिस्से को बुरी तरह से नोंचकर खाया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को

कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मगरलोड थाना इलाके के सिंगपुर बस्ती में तेंदुआ नजर आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तेंदुआ रात के वक्त चहलकदमी करते हुए शिकार की तलाश में गांव में घुसता है। कुछ दिन पहले सिंगपुर बस्ती में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए के आने की तस्वीर कैद हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि तेंदुआ मकान में घुसने की जगह तलाश कर रहा है। मकान में घुसने की जब जगह तेंदुए को नहीं मिलती तो वो वहां से रफूचक्कर हो जाता है।इसी तेंदुए ने अब महिला को शिकार बनाया है।

बाजार से लौट रहे युवक पर झाड़ियों में छिपे तेंदुए का हमला

कांकेर। तेंदुए ने एक ग्रामीण युवक पर हमला कर दिया। जिससे युवक की जान चली गई। घटना कांकेर वन परिक्षेत्र के कोदागांव इलाके की है। मृतक की पहचान कोंदागांव बाजारपारा निवासी द्वारका भोयर के रूप में हुई है।

ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को द्वारका भोयर बाजार गया था। वहां से अपना काम खत्म करने के बाद पैदल अपने घर लौट रहा था। इस दौरान कुछ देर के लिए वह सड़क किनारे आराम करने के लिए रुका। इसी बीच झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद युवक का शव सड़क से करीब 200 मीटर अंदर जंगल में क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी रहमान खान ने कहा घटना स्थल पहुंचकर पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। प्रकरण तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वन विभाग की टीम गस्त कर रही है।

कांकेर में तेंदुए, भालू और हाथी का आतंक आए दिन देखने को मिलता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल वन विभाग तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में 15-20 दिसंबर के बीच लग सकती है आचार-संहिता

रायपुर। निकाय चुनाव के लिए नाम तो बहुतों के उछल रहे हैं पर जब तक आरक्षण के चलते स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक केवल दावेदारी ही रहेगी। दावेदार भी इसीलिए सहमे हुए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए 15 से 20 दिसंबर के बीच आचार संहिता लागू हो सकती है। निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची 11 दिसंबर तक फाइनल की जा सकती है। निकायों को लेकर जब 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके तीन से चार दिन बाद आचार संहिता लागू हो जायेगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी हो गया है। इसके अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत ही रखी गई है। इससे यह ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व भी मिलेगा। हालांकि, जहां एससी-एसटी की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

हज प्रशिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि हज कमेटी ऑफ़ इंडिया मुंबई के सर्कुलर 15 से प्राप्त सूचना अनुसार हज 2025 के लिए जाने वाले हज यात्रियों को हज की ट्रेनिंग देने हेतु हज प्रशिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन 13/12/2024 रात्रि 23ः59 बजे तक आमंत्रित किये गए है। हज प्रशिक्षक हेतु निर्धारित अर्हताए व नियमावली का सम्पूर्ण विवरण हज कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-4266646 पर संपर्क किया जा सकता है।

धीवर समाज का प्रदेश स्तरीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन 8 को

रायपुर। छत्तीसगढ़ धीवर समाज महासभा का प्रदेश स्तरीय युवक-युवती परिचय 8 दिसंबर को कोटनी परगना के ग्राम नवागांव- मंदिरहसौद में होगा। बैठक में समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश धीवर, कोटनी परगना के अध्यक्ष सहदेव धीवर सहित 32 परगना के अध्यक्ष प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। रायपुर परक्षेत्र के युवा अध्यक्ष महेशरू ढीमर, सचिव लक्की रिगरी और कोषाध्यक्ष नीरज धीवर के अनुसार इस परिचय सम्मेलन की तैयारी में आईटी टीम रायपुर, नवागांव एवं कोटनी परगना के युवा जोरशोर से लगे हुए हैं।

चखना संचालक बारले गिरफ्तार 10 हजार का शराब भी जप्त

रायपुर। ग्राम छोटे उरला शराब दुकान के पास चखना सेंटर में लोगों को अवैध रूप से शराब पिला रहे संचालक दिनेश बारले को अभनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से शराब भी जप्त किया गया। इसी प्रकार शराब दुकान और उसके आसपास अवैध शराब पीने और पिलाने वाले आधा दर्जन लोगों के पास से 10 हजार का शराब और कोचिएं को बाईक सहित पकड़ा है। उनके खिलाफ आबकारी एक्ट 36 सी के तहत मामला दर्ज किया गया। अभनपुर पुलिस ने ठेलों पर अवैध शराब परोसने वाले दिनेश बारले, प्रदीप चर्तुवेदी, ताम्रध्वज साहू, घनश्याम पाल, परमा देवांगन आरंग पुलिस ने फगुराम साहु, चंद्रशेखर बंजारे, धनेश्वर धीवर, किशोर जलक्षत्री, हरिशचंद्र निषाद, मौदहापारा इलाके से युनूश खान, सागर नायक के खिलाफ आबकारी एक्ट 36 सी का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

महादेवघाट एनीकट परिक्षेत्र के कार्यों के लिए 18 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर जिले के विकासखंड धरसीवा के अंतर्गत महादेवघाट एनीकट परिक्षेत्र का सुरक्षा विकास एवं सौन्दर्यकरण कार्य के लिए 18 करोड़ 15 लाख 47 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से एनीकट के कार्य के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर एजेसी बनाई गई है।

हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लाक, 9 ट्रेनें रद्द

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंध-तिल्दा नेवरा सेक्शन में रिलीविंग गर्डर की डी लांचिंग के लिए ट्राफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के लिए 6 दिसंबर को रात्रि 22 बजे से 7 दिसंबर को 2 तक 4 घंटे का ब्लॉक अप लाइन में और 3 घंटे 30 मिनट का ब्लॉक मिडल लाइन में लिया जाएगा। 9 दिसंबर को 1 बजे से 4ः30 बजे तक 3 घंटे 30 मिनट का डाउन लाइन में ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

रद्द होने वाली गाडियां- 6 एवं 9 दिसम्बर, को गाडी संख्या 08719 बिलासपुर-रायपुर मेमू। 6 दिसम्बर को गाडी संख्या 08727 बिलासपुर-रायपुर मेमू। 7 दिसम्बर को गाडी संख्या 08261 बिलासपुर-रायपुर पैसेंजर। 7 दिसम्बर को गाडी संख्या 08275 रायपुर-जूनागढ़ रोड पैसेंजर। 8 दिसम्बर को गाडी संख्या 08276 जूनागढ़- रायपुर रोड पैसेंजर। 8 दिसम्बर को गाडी संख्या 08280 रायपुर-कोरबा पैसेंजर। 9 दिसम्बर को गाडी संख्या 08728 रायपुर-बिलासपुर मेमू। 9 दिसम्बर को गाडी संख्या 08734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमु। 9 दिसम्बर को गाडी संख्या 08733 गेवरा रोड- बिलासपुर मेमु।

सांस्कृतिक विविधता हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है: राज्यपाल

राजभवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया 5 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस

रायपुर। राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुरुवार को छत्तीसगढ़ सहित 05 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है। राजभवन में राज्यपाल श्री डेका के मुख्य आतिथ्य में भारत के राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक-दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले इन राज्यों के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

कार्यक्रम में राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम हमारे देश के विभिन्न राज्यों में बसे निवासियों को एक सूत्र में पिरोने का अद्भुत प्रयास है, जिससे भारत की एकता और अखंडता और अधिक मजबूत होगी। डेका ने कहा कि हर राज्य का स्थापना दिवस उस राज्य के इतिहास में और विकास की यात्रा का महत्वपूर्ण दिन होता है। राज्य की समृद्धि और विकास का गवाह यह दिन, हमें अपने राज्य की स्थापना के मूल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता दिखाता है।

डेका ने सभी राज्यों की विशिष्टताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक वातावरण और भौगलिक स्थिति अदभुत है। यहां पर्यटन की बहुत संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जायेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के चावल की भी प्रशंसा की। आजादी की लड़ाई में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए, वहां के वीर सेनानियों को याद किया। पंजाब राज्य के लोगों की दान शीलता का जिक्र किया। पंजाब का इतिहास बलिदानों से भरा हुआ जिस पर हर देशवासी को गर्व है। पंजाब और हरियाणा राज्य ने हरित क्रांति के माध्यम से देश को एक नई ऊर्जा दी। डेका ने कहा कि इन सभी राज्यों ने भारत के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग, कला खेलकूद, शिक्षा या पर्यटन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में, इन राज्यों का योगदान सराहनीय है। हम सब को मिलकर अपने राज्यों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे का भी ध्यान रखना है। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सभी राज्यों की संस्कृति एवं लोक परंपरा आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ का लोक-नृत्य सुआ, सरहुल नृत्य, गेड़ी नृत्य, नाचा, पंजाब का भांगडा, गिद्धा, हरियाणा का घूमर तथा मध्यप्रदेश की जनजातियों के राई नृत्य ने अतिथियों का मन मोह लिया। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पंजाब के प्रतिनिधियों ने श्री डेका को सरोपा भेंट किया। छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में पद्मश्री अनुज शर्मा, मध्यप्रदेश के श्री आकाश दीप गुप्ता, पंजाब के प्रतिनिधि श्री दलजीत चावला, हरियाणा के प्रतिनिधि श्री अमित अग्रवाल को राज्यपाल ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव श्री यशंवत कुमार, विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय, संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम एवं इन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के छत्तीसगढ़ में निवासरत, युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कांग्रेस की लगातार हार पर भाजपा ने पूछा सवाल एक के बाद एक कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन?

कांग्रेस में पसरा सन्नाटा, जनता के साथ किए धोखे का मिल रहा फल : केदार

रायपुर। प्रदेश सरकार में वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर इस बात को लेकर तीखा तंज कसा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में हारने के बाद भी कांग्रेस में ऐसा एक भी नेता सामने नहीं आ रहा है, जो इस करारी हार की जिम्मेदारी ले या फिर जिम्मेदारी तय करे। श्री कश्यप ने कहा कि इस उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में एक बार फिर सन्नाटा पसरा हुआ है।

कश्यप ने कहा कि पिछले साल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी हार देखी और केवल 35 सीटों पर ही सिमटकर रह गई जबकि 54 सीटों के साथ भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाजपा को वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा मिला। उसके बाद इसी वर्ष के मध्य में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी अपने दिग्गज पूर्व मंत्रियों को मैदान में फिर उतारा। भूपेश बघेल खुद

राजनांदगाँव से लड़े, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से लड़े, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के अलावा राहुल गांधी के करीबी जो विधायक जेल में है, वह भी लड़े। ये सारे कांग्रेसी दिग्गज लोकसभा का चुनाव हार गए! श्री कश्यप ने कहा कि रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस नेता यह दावे कर रहे थे कि भाजपा की सरकार काम नहीं कर रही है और कांग्रेस की इकतरफा जीत होगी, तो रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला, उससे ज्यादा की लीड के साथ भाजपा ने यह उपचुनाव जीता है।

कश्यप ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लगातार हार के बाद हार से कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया है। कांग्रेस पूरी तरह से हताश-निराश हो चली है, जनता के द्वारा नकारी गई पार्टी बन गई है। विपक्ष के रूप में कोई रचनात्मक काम कांग्रेस नहीं करती और केवल छत्तीसगढ़ में उसने हिंसा फैलाने के प्रयास किए, अपराध बढाने के प्रयास किए, लेकिन अपनी बदनीयती से भरे इरादों में कांग्रेस सफल नहीं हो रही है और जनता बार-बार बार-बार कांग्रेस के गाल पर तमाचे पर तमाचे मार रही है। श्री कश्यप ने कहा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस में कोई भी हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज तक कोई नेता सामने नहीं आया, जिसने यह कहा कि हर के लिए मैं जिम्मेदार हूँ याफिर कांग्रेस नेतृत्व ने यह साहस तक नहीं दिखाया है कि वह इस करारी हार की जिम्मेदारी तय कर सके। कांग्रेस की जो ऐसी दुर्गति है, इससे कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।

निकाय चुनाव पर सियासत, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव बोले-

पीएम और सीएम इनडायरेक्ट चुना जा सकता है तो निकायों में क्यों नहीं?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ओबीसी सर्वे में गड़बड़ी का संदेह जताते हुए कहा कि सर्वे में ओबीसी की आबादी कम बताई गई है। सरगुजा में ओबीसी सर्वे में अनारक्षित वर्ग के लोगों ने अपना नाम जुड़वाया है। ऐसे में कई इलाकों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेता अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यदि इनडायरेक्ट चुना जा सकता है तो निकायों में क्यों नहीं?

सिंहदेव ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग नीचे हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं, ये कैसा तर्क है। इसमें वन नेशन वन प्रक्रिया क्यों नहीं करते। दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि प्रणाली बदलती रही है। आजकल ऑपरेशन लोटस चलन में है। नियम कानून आए, लेकिन रुक नहीं रहा है। सभी असफल रहा। जीतने कड़े कानून बना सके बनाना चाहिए। यदि कोई दल बदलता है तो आगे कुछ समय तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देना चाहिए।

नारायणपुर के एकलव्य विद्यालय के वायरल वीडियो को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने

शर्मनाक बताया है। वन मंत्री केदार कश्यप के वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई करने के बयान पर सिंहदेव ने कहा, यदि व्यवस्था ऐसी है तो अमानवीय है। इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

बीजेपी के जनादेश दिवस को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह ने कहा है कि काम नहीं के बराबर हुआ है। एक महतारी योजना ही लागू किया। बिजली से लोग परेशान हैं। शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई प्रगति नजर नहीं आ रहा है। कई क्षेत्रों में स्थिति और खराब हुई है।

धान खरीदी पर धनेंद्र साहू ने सरकार पर साधा निशाना

- कहा- किसानों से न 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही, न ही एकमुश्त मिल रहा 3100 रुपए

रायपुर। कांग्रेस की धान खरीदी केंद्र चलो अभियान पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था बदहाल है। किसानों में नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश की धान खरीदी की जांच लिए के लिए समिति बनाई है। रायपुर की समिति ने खरीदी केंद्रों का जायजा लिया, जिसमें पता चला कि धान तौलने में अनियमितता बरती जा रही है।

धनेंद्र साहू ने कहा कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है। टोकन के लिए ऑनलाइन खरीदी की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन ऐप में कई गड़बड़ियां है। धान खरीदी का एक मुश्त 3100 रुपए किसानों को नहीं दिया जा रहा है। धान का उठाव नहीं होने के कारण धान

खरीदी केन्द्रों में हो कई परेशानियां हो रही है। धान खरीदी केंद्र में एटीएम की सुविधा विफल है। प्रेसवार्ता में पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।

हॉर्स ट्रेडिंग वाले विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेनद्र साहू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, धन बल की राजनीति कर सरकारों को बीजेपी ने गिराया। बीजेपी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग करती है। अन्य राज्यों में भी देखा गया। दोनों ही पद्धति से कांग्रेस जीती। किरणमयी नायक , प्रमोद दुबे महापौर बने। अप्रत्यक्ष प्रणाली से कांग्रेस के महापौर बने, बीजेपी डरी हुई है। अपना इतिहास ही देखना चाहिए। दूसरों पर आरोप लगाना बंद करें।

विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान

- कहा- मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार

रायपुर। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर के दिल्ली दौरे से छत्तीसगढ़ के सियासत में उबाल आ गया। विधायक चंद्राकर ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है। चर्चा है की मंत्री के दो खाली पड़े पद में एक नाम अजय चंद्राकर का भी हो सकता है।

इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री बनना, नहीं बनना कब बनना और कैसे बनना है। यह विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इस बारे में मुझे ना कुछ बोलना

है। ना ही कुछ कहना है। खाली विभाग जो है। वे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं।

दिल्ली दौरे को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गए थे। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर जा सकते हैं, जो केंद्र सरकार से संबंधित है। मैंने अपने सांसद से लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री तोखन साहू के साथ में क्षेत्र की जो समस्याएं थी, केंद्र सरकार के समक्ष उसके बारे में ही चर्चा हुई।

कांग्रेस के धान खरीदी केंद्रों को लेकर प्रेस वार्ता को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- कोई गंभीर बात वो नहीं बता सके हैं। सुचारू रूप से काम चल रहा है। वहीं धान खरीदी कम होने को लेकर कहा, धान की कटाई पूरी तरह हुई नहीं है। समय बढ़ाने के आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निर्धारित समय में पूरी खरीदी हो जाएगी।

बीजेपी की सरकार बनने के बाद निकायों में विकास नहीं होने के बयान पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विकास जिसका होना है, उसका तो पूरा विकास हो गया। रायपुर में कितने तालाबो का सौंदर्यीकरण हुआ है देखिए। ये कांग्रेस का विकास है रायपुर में।

अपराध और धान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इस सवाल पर विधायक चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस हमलावर रहेगी। एक प्रेस वार्ता लेकर एक बार क्रोध में उन्होंने आंदोलन किया। टोल नाका के लिए टोल नाका में 15 से 20 कांग्रेसी थे, कुछ पुलिस वाले थे। पहले जन समर्थन लेना चाहिए, उसके बाद करें। केवल समाचार पत्रों में, मीडिया भर में वे आंदोलित हैं। जमीन में कहीं कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है।

विधायक अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता हैं, चरण दास महंत। उनके अनुभव का ही कांग्रेस उपयोग करती, तो यह गति नहीं होती। जिस गति में आज कांग्रेस है।

खेल अलंकरण को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था

रायपुर। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खेल अलंकरण समारोह को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था। हमने चार साल का अलंकरण समारोह आयोजित किया है। खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया है। छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना लागू किया है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे लाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर ओलंपिक चल रहा है। जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर आयोजन होगा। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय भी आएंगे।

इसके अलावा खेल मंत्री वर्मा ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची तैयार हो रही है। नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण का

प्रावधान रहेगा।

भू-प्रकरणों के निराकरण को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में जिओ रेफरेंसिंग के माध्यम से समस्या दूर करने का प्रयास जारी है। भू-प्रकरण के निराकरण के लिए 3 महीने और 6 महीने का समय तय है। केस नहीं सुलझने पर अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जा सकते है प्रार्थी। अविवादित प्रकरण 3 महीने के भीतर और विवादित 6 महीने के भीतर निराकरण करना है।

पटवारियों की समस्या पर मंत्री वर्मा ने कहा कि किसानों के लिए कार्ड बन रहा है। किसानों के अधिकार की जानकारी उनके कार्ड में होगी। बेहतर प्रयास किया जा रहा है।

रायपुर में खिलाड़ियों के लिए खेलने की जगह कम हो रही है। खाली मैदानों को घेरा जा रहा है। इसे लेकर खेल मंत्री वर्मा ने कहा कि मैदानों के लिए हमने सचिव के माध्यम से लिखा है। सचिव के माध्यम से हमने निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्देश दिए हैं। 5 एकड़ कम से कम वहां पर जमीन आरक्षित की जाए। ब्लॉक लेवल में दो एकड़ जमीन आरक्षित की जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए खेलने के लिए व्यवस्था की जाए। हमारे विष्णु देव साय की एक साल की उपलब्धि बहुत है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं पूरा हुई है।

रेलवे मंत्रालय द्वारा कांकेर जिले में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की पहल

रायपुर। रेल मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में रेल कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत, दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना (कुल लंबाई 235 किमी) को दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। पहले चरण में दल्लीराजहरा से रावघाट (95 किमी)।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड, कबीरधाम (छ.ग.)

निविदा निरस्त सूचना

इस कार्यालय के निविदा सूचना क्रमांक 09 दिनांक 19.11.2024 को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।
पूर्व जी. क्रमांक 242503902 दिनांक 21.11.2024

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
कबीरधाम (छ.ग.)
जी-242504363

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कांकेर मण्डल, कांकेर
Email - sepwdkanker.2010@rediffmail.com / se.kanker@nic.in, Fax No. 07868-224040

-: ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना :-

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित भवन कार्य हेतु दिनांक 20.12.2024 समय 17:30 बजे तक ऑनलाईन (Online) निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	एन.आई.टी. नंबर	टेण्डर नंबर	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3	4	5
01	108	162192	जिला न्यायालय परिसर, कांकेर में अधिवक्ताओं के लिए बार रूम का निर्माण कार्य।	75.23 लाख
02	109	162193	न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कांकेर के लिए 01 नग सी-टाईप शासकीय आवासगृह का निर्माण कार्य।	66.39 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञिस, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट बेव पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय बेवसाईट https://eproc.cgstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है। डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 20.12.2024 है।
नोटः- प्रथम आमंत्रण

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग कांकेर
मंडल कांकेर
जी-242504334/8

यूक्रेन युद्ध पर बाइडन ने ट्रंप को फंसा दिया

रहीस सिंह

सोवियत संघ के पतन के एक साल बाद ही 'द एंड ऑफ हिस्ट्री' की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन यह पश्चिमी दुनिया का खेल था, क्योंकि उस इतिहास का अंत कभी हुआ ही नहीं। हां, दुनिया जरूर एकध्रुवीय हो गई, जिसमें अमेरिका और पश्चिम को सोवियत संघ से मिलने वाली चुनौती खत्म हो चुकी थी। हालांकि ऐसा भी नहीं रहा कि वे चुनौतीविहीन हो गए। पश्चिमी दुनिया, विशेषकर यूरोप 'सभ्यता के संघर्ष' के दौर से गुजर रहा है, भले ही इसे सैद्धांतिक स्तर पर स्वीकार न किया जाए। मध्य-पूर्व खतरनाक मोड़ पर है और यूरेशिया युद्ध का मैदान बना हुआ है। इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका का बहुत कुछ दांव पर है, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन और उसके सहयोगी बिना किसी चुनौती के आगे बढ़ रहे हैं? रूस-यूक्रेन युद्ध 'रेड लाइन' पार करता दिख रहा है। इसके चलते दुनिया 'न्यू वॉर जोन' में पहुंचती लग रही है। यह वक्त शीत युद्ध के बाद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच रही है? हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा। उनका कहना है कि मॉस्को अपने नए हथियारों का प्रयोग जारी रखेगा। डॉनल्ड ट्रंप एक दिन में यह युद्ध खत्म कराने की बात कह रहे थे, लेकिन उनके शपथ लेने से पहले जो स्थितियां बन रही हैं, वह उनका साथ देती नहीं लगतीं। यह 'वॉर गेम' अमेरिका की ही देन है। बाइडन प्रशासन ने ही यूक्रेन को अनुमति दी है कि वह अमेरिकी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से रूस पर डीप स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से तर्क दिया गया कि अमेरिकी नीति में यह बदलाव कुर्स्क सीमा क्षेत्र में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती के कारण आया है। ध्यान रहे कि कुर्स्क रूस की सीमा में है, जहां यूक्रेन ने अगस्त से ही करीब 1000 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। लेकिन, असल वजह यह नहीं मालूम पड़ती। असली कारण अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हार और रिपब्लिकन पार्टी की जीत में छुपा है। शायद जो बाइडन अगले साल 20 जनवरी को ट्रंप को कांटों का ताज सौंपना चाहते हैं। इससे ट्रंप की 'पीस स्ट्रैटेजी' प्रभावित होगी, जो अमेरिकी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इससे ट्रंप की लोकप्रियता गिरेगी और वह चुनौतियों से घिरने लगेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस निर्णय की प्रतिक्रिया में रूस ने 'रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन' पेश कर दिया, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। पूतिन का कहना है कि यह युद्ध अब क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि वैश्विक टकराव में बदल चुका है। हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध सही अर्थों में पहले भी क्षेत्रीय विवाद के रूप में नहीं दिख रहा था। रूस के खिलाफ यूक्रेन नहीं, अमेरिका और उसके सहयोगी हैं। पूतिन के 'न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन' के कई आयाम हैं, जो खतरनाक हैं। एक तो यही कि कोई ऐसा देश जिसके पास स्वयं परमाणु हथियार न हों, लेकिन वह किसी परमाणु हथियार संपन्न देश के साथ मिलकर हमला करता है तो रूस इसे अपने ऊपर संयुक्त हमला मानेगा। अगर रूस को पता चला कि दूसरी तरफ से उस पर मिसाइल, ड्रोन या हवाई हमले हो रहे हैं तो वह अपने परमाणु हथियारों से जवाब दे सकता है। इसके अलावा इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कहा गया है कि अगर किसी देश ने नया सैन्य गठबंधन बनाया, पुराने को विस्तार दिया, रूस की सीमा के करीब सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, उसे प्रयोग में लाया या फिर रूसी सीमा के आसपास किसी तरह की सैन्य गतिविधियां कीं, तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस पहले भी 'न्यूक रेस्पॉन्स' की धमकी दे चुका है। बीते मार्च महीने में रूस में चुनाव के पहले भी पूतिन ने कहा था, 'रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है।' ऐसे में बाइडन के कदम के पीछे मकसद जो भी हो, लेकिन दुनिया को भली-भांति समझ लेना चाहिए कि यदि रूस ने न्यूक्लियर हमला करने का विचार किया तो परिणाम भयावह होंगे। न्यूक्लियर बम के एक्सप्लोजन के साथ ही ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी रिएक्शन होता है, जिसे 'म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन' (मैड) कहा जाता है। साधारण शब्दों में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। रूस यदि न्यूक रेस्पॉन्स करता है तो दुनिया संकट के मुंह में चली जाएगी।

कौन हैं, जिन्हें भारत पर विश्वास नहीं

बलबीर पुंज

हालिया घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि देश की राजनीति में एक वर्ग को भारत पर ही भरोसा नहीं है। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में दलों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना स्वाभाविक है और यह स्वस्थ जनतंत्र का प्रतीक भी है। परंतु भारत, जोकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है वहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों का भाजपा-संघ विरोध, देश और उसकी संस्थाओं के प्रति शत्रुता और घृणा में परिवर्तित हो गया है। चाहे चुनाव आयोग हो,न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो या फिर देश की उज्जवल औद्योगिक क्षमता राजनीतिक और वैचारिक कारणों से विश्व में इन सबकी छवि को कलंकित और धूमिल करने का संयुक्त प्रयास इसका जीता जागता उदाहरण है।

हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगियों की बौखलाहट चरम पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 26 नवंबर को यहां तक कह दिया, 'हमें बैलेट पेपर की वापसी के लिए आंदोलन शुरू करना चाहिए।' चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में भी पराजय के संकेत मिल गए थे। यही नहीं, गत दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने संबंधित अर्जी पर न सिर्फ याचिकाकर्त्ता को कड़ी फटकार लगाई थी, बल्कि इसके माध्यम से राजनीतिक दलों को भी संदेश देते हुए कहा था कि जब चुनाव हार जाते हैं तो ई.वी.एम. खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो चुप्पी। हार का ठीकरा

ई.वी.एम. पर फोडऩा ठीक नहीं। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे, तब क्रमश: जम्मू-कश्मीर और झारखंड चुनाव का भी फैसला आया था, जिसमें कांग्रेस समर्थित गठबंधन विजयी रहा था। इसी दौरान गांधी-वाड्रा परिवार की प्रियंका गांधी भी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रचंड मतों के साथ जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं।

विपक्षी दल देश में उस चुनाव आयोग और ई.वी.एम. की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं जिसे दुनियाभर में सराहा जाता है। हरियाणा-महाराष्ट्र चुनाव के जनमत को मानने से इंकार करना और निर्वाचन प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाने का प्रयास, असल में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की कुंठा, अपने सहयोगियों को कमतर आंकना, असहमति के प्रति असहिष्णु चरित्र और जनमानस से उनके कटाव को ही दिखाता है। इसी कांग्रेस ने अपने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर संसद नहीं चलने दी। इसका प्रमुख कारण अमरीकी अदालत द्वारा भारतीय कंपनी अडानी समूह के खिलाफ आरोप लगाना रहा।

यह दिलचस्प है कि स्वयं अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, तब कांग्रेस आदि विरोधी दल उसी अमरीकी न्याय प्रणाली पर अंध-विश्वास कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक दिसंबर को अपने बेटे हंटर को 100 से अधिक अपराधों, जिनमें नशीली दवाओं और व्यावसायिक अपराध शामिल हैं, उसे 'राजनीति' से 'संक्रमित' बताते हुए बिना शर्त क्षमादान दिया है। यह अमरीकी न्याय प्रणाली और उसके खोखले लोकतंत्र की सच्चाई है। दुर्भाग्य से राहुल अपने विदेशी दौरों में इन्हीं पश्चिमी-अमरीकी देशों से भारत में अनादिकालीन लोकतंत्र की तथाकथित 'रक्षा' करने का आह्वान करते हैं।यह जांच का विषय है कि अडानी ने अपने व्यापारिक विस्तार में भ्रष्टाचार का सहारा लिया या नहीं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि अमरीका और चीन सहित शेष विश्व के बड़े औद्योगिक घरानों ने विश्व में अपना व्यापारिक साम्राज्य इसी तरह स्थापित किया है?

अडानी पर कथित रिश्वत देने का आरोप केवल व्यापारिक ईमानदारी के उल्लंघन से जुड़ा है या मामला कुछ और है। सच तो यह है कि अडानी समूह एशिया, अफ्रीका और अमरीका में बड़े स्तर पर वैश्विक बंदरगाह, हवाई अड्डों और ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बना रहा है, जो मजबूत और महत्वाकांक्षी भारत के वैश्विक उभार का प्रतीक हैं। स्वाभाविक है कि वर्ष 2014 से भारतीय उद्यम क्षमता के वैश्विक फैलाव से 'व्हाइट मेन बर्डन' मानसिकता प्रेरित औपनिवेशिक वर्ग और साम्राज्यवादी चीन बौखला रहा है। इनका उद्देश्य सिर्फ अडानी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि समस्त भारत, उसकी उद्यम शक्ति और वित्तीय निकाय प्रणाली को भी संदिग्ध बनाकर धराशायी करना है। यह चिंताजनक है कि भारत में विपक्षी दल का बड़ा हिस्सा (कांग्रेस सहित) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अंधी-घृणा के कारण प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से उसी भारत-विरोधी वैश्विक जमात का भोंपू बनता जा रहा है।

देश की तरक्की में नीतिगत सुधारों के साथ भारतीय उद्यम क्षमता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे वामपंथ प्रेरित समाजवाद के कारण 1990 के दशक तक पनपने नहीं दिया जा रहा था। यह रोचक है कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को अमरीकी अदालतों पर विश्वास है, परंतु वह भारतीय न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। इस मानसिकता के पीछे वे निर्णय हैं, जिनसे इनका राजनीतिक-वैचारिक एजेंडा ध्वस्त होता है। इस बार इनके निशाने पर हाल ही में सेवानिवृत हुए मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे न वर्ष केवल 2019 में अयोध्या मामले में श्रीरामलला के पक्ष में फैसला देने वाली खंडपीठ का हिस्सा थे, बल्कि बकौल सी.जे.आई. उन्होंने 1991 के 'पूजा स्थल अधिनियम' पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह कानून किसी पूजास्थल के मजहबी चरित्र का पता लगाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता। इससे पहले अप्रैल 2018 में कांग्रेस और वामपंथियों सहित कुछ विपक्षी दलों ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, भारतीय लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। आज यही संस्थाएं जब स्वतंत्र होकर, संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर काम कर रही हैं और देश में दशकों तक दबे वैकल्पिक विचार-विमर्श को जनस्वीकृति मिल रही है, तब कांग्रेस और उसके सहयोगियों का कुंठित होना समझ में आता है।

एकात्मता के स्वर

गया

एक समय गय नामक असुर ने भगवान विष्णु की भारी तपस्या की। श्री हरि ने तप से प्रसन्न हो वरदान देने को कहा, तब गय ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं सब तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊँ। श्री प्रभु तथास्तु कहकर चले गये। फिर तो सभी मनुष्य उस दैत्य (भक्त) का दर्शन करके भगवान के समीप जा पहुँचे। पृथ्वी सूनी हो गयी। चिन्तित सभी देवता ब्रह्मा सहित श्री हरि के पास गये तब भगवान् ने कहा, ब्रह्मा जी! तुम गयासुर के पास जाकर यज्ञभूमि के लिए उसका शरीर माँगो। सभी देवों ने अतिथि बनकर जब यज्ञ के लिए उसके शरीर की याचना की, तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरम्भ किया। जब पूर्णाहुति का समय आया तब गयासुर का शरीर चंचल हो उठा, तब ब्रह्मा जी ने गय के विचलित होने की बात श्री हरि से कही। विष्णु ने कहा, ब्रह्मादि देवताओं ! धर्म और धर्मवती से पैदा हुई कन्या धर्मव्रता का विवाह महर्षि मरीचि से हुआ था। कुशा-पुष्प आदि लेकर आने से थके महर्षि के जब वह चरण दबा रही थी तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गये। धर्मव्रता दुविधा में पड गयी तब उसने पति की चरण सेवा को छोडकर महर्षि मरीचि के पिता और अपने श्वसुर ब्रह्मा जी की पूजा की। उसी अवसर पर नींद टूटने से पास धर्मव्रता को न देख शाप देते हुए कहा, तू शिला हो जायेगी। तब अपने को निर्दोष जान उसने भी मरीचि को शाप दिया कि आपको भी शिव से शाप की प्राप्ति होगी। धर्मव्रता ने शाप को पृथक् रख कर विष्णु की आराधना की। तब भगवान् ने कहा कि मरीचि का शाप अन्यथा नहीं हो सकता है तुम्हें शिला होना ही पड़ेगा। अब मेरी कृपा से समस्त देवता और देवियाँ तुम्हारे ऊपर हमेशा विराजमान रहेंगी। भगवान् विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, इसी देवमयी शिला को तुम गयासुर के शरीर के ऊपर रख दो। इस देवमयी शिला के रखने पर भी जब वह हिलने लगा तब रुद्र आदि देव शिला पर जा बैठे। तब भी वह हिलता ही रहा।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

गतांक से आगे...

तथा वे लोकान्तर-गमन, परकाय-प्रवेश सूर्य-चन्द्रादि में प्रवेश कर सकते हैं- यह स्वयं दयानन्द जी ने अपने यजुर्वेद भाष्य में स्वीकार किया है, यथा: (भावार्थ) जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है तब अणिमादि सिद्धि उत्पन्न होती हैं। उसके पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से अभीष्ट स्थानों को जा सकता है अन्यथा नहीं।

हमें यहां दयानन्द जी के शब्दों में अणिमादि आठ सिद्धियों का वर्णन इसलिए करना पड़ा कि इस प्रकार के चमत्कारों को आर्यसमाज के अतिरिक्त शेष सभी आस्तिक सम्प्रदाय तो मानते ही हैं। केवल यही एक दल है जो चार्वाक की भांति प्रत्यक्ष का ही समर्थन करता है।

अत: हमारे इस उद्धरण से उसे भी योगसिद्धि का विश्वासी होना पड़ेगा। इस प्रकार त्रिकालज्ञ योगीराज व्यास जी ने भविष्यत्कालवर्ती श्री बुद्ध भगवान् का वर्णन किया है, यही निश्चित है।

(2) तौजुक जहांगीरी नाम किताब में लिखा है कि आलू, तम्बाकू और गोभी- ये तीनों चीजें जहांगीर बादशाह के पिता यानी अकबर के जमाने में एक अमेरिकन पादरी अपने देश से लाया था। अकबर का राज्यकाल विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वभाग में माना जाता है, परन्तु पद्मपुराण और ब्रह्माण्डपुराण में तम्बाकू का वर्णन मिलता है! यथा-

(क) तमालं भक्षितं येन स गच्छेन्नरकार्णवे।

(ख) धूम्रपानरतं विप्रं दानं कुर्वन्ति ये नरा: । दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणो ग्रामशूकर:।। (ब्रह्माण्ड) (पद्मपुराण) - इसलिए उपर्युक्त दोनों पुराण अकबर के बाद बने हैं, व्यासोक्त नहीं। (2) इस आक्षेप का मूल पुराणों में तमाल और धूम्रपान इन दो शब्दों का आ जाना है। प्रथम तो प्रतिवादियों ने उक्त दोनों श्लोकों का पूरा पता नहीं लिखा।

क्रमश: ...

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

निधि अविनाश

अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। वह एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और दलित नेता थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। पश्चिमी भारत के एक दलित महान परिवार में जन्मे अंबेडकर को अपने उच्च जाति के स्कूली साथियों द्वारा कई बार अपमानित किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। बड़ौदा (अब वडोदरा) के गायकवाड़ (शासक) द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित, अम्बेडकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की।

उन्होंने गायकवाड़ के अनुरोध पर बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन, फिर से उनके उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा उनपर दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया और दलितों के बीच अपना नेतृत्व स्थापित किया। दलितों (या हरिजन, जैसा कि गांधी उन्हें कहते थे) के लिए बोलने के महात्मा गांधी के दावे का विरोध करते हुए, अम्बेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स (1945) लिखा। 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई, अछूतों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त किया। 1951 में उन्होंने सरकार में अपने प्रभाव की कमी से निराश होकर इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1956 में, हिंदू सिद्धांत में अस्पृश्यता के कारण निराशा में, उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और नागपुर में एक समारोह में लगभग 200,000 साथी दलितों के साथ बौद्ध बन गए। अम्बेडकर की पुस्तक द बुद्धा एंड हिज़ धम्म 1957 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई, और इसे 2011 में द बुद्ध एंड हिज़ धम्म: ए क्रिटिकल एडिशन के रूप में एक बार फिर प्रकाशित किया गया, जिसे आकाश सिंह राठौर और अजय वर्मा द्वारा संपादित, प्रस्तुत और एनोटेट किया गया। संविधान के रचियता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। भारत की संविधान दुनिया का सबसे अधिक शब्दों वाला संविधान है लेकिन आपको बता दें कि संविधान के रचियता डॉ. भीमराव अम्बेडकर अपने इस लिखे हुए संविधान को जला देना चाहते थे। बताया जाता है कि 23 सितंबर 1953 को राज्यसभा में अम्बेडकर ने कहा था कि छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा यह गर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे दोस्त कहता है कि मैंने संविधान बनाया है लेकिन आपको बताना चाता हुं कि अपने हाथों से लिखी इस संविधन को जलाने वाला व्यक्ति में ही होंगा। 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में अम्बेडकर ने संविधान को जलाने के पीछे कारण बताया और कहा कि हमने भगवान के रहने के लिए मंदिर बनाया कि भगवान उसमें आकर रहने लगे लेकिन हुआ क्या वहां भगवान की जगह राक्षस आकर रहने लगे। हमने ये मंदिर राक्षस के लिए तो बनाया नहीं था। हमने तो इसे देवताओं के लिए बनाया था। अब हमारे पास इसे तोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसलिए मैनें कहा था कि मैं संविधान को जला देना चाहता हूं।

बोफोर्स घोटाले की फाइल फिर से खुलेगी!

अभिनय आकाश

1980 के दशक का विवादित केस बोफोर्स फिर से खुल सकता है। दरअसल, सीबीआई ने अमेरिका को न्यायिक अनुरोध भेजने वाली है। इससे पहले अमेरिकी जासूस माइकल हसनन ने एक टीवी चैनल पर कहा था कि वो इस बारे में जानकारी साझा करना चाहते हैं और इसी के बाद सीबीआई की ओर से पहल की गई है। इस केस को 2011 में बंद कर दिया गया था और आरोपी राजीव गांधी व कात्रोची को बरी कर दिया गया था। लेकिन 13 साल बाद फिर से खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जांच एजेसी सीबीआई बोफोर्स मामले मे निजी जासूस माइकल हर्शमैन से अमेरिका को एक न्यायिक अनुरोध भेजेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हर्शमैन ने 1980 के दशक के 64 करोड़ रुपये के कथित बोफोर्स रिश्वत कांड के बारे में अहम जानकारी भारतीय एजेंसियो के साथ साझा करने की इच्छा जताई की थी। सीबीआई ने एक विशेष अदालत को भी इस बारे में सूचित किया है, जो मामले में आगे की जांच के लिए एजेंसी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि लेटर रोगेटरी भेजने की प्रक्रिया इस साल अक्टूबर में शुरू की गई थी। अमेरिका को औपचारिक अनुरोध भेजने में लगभग 90 दिन लगने की संभावना है। लेटर रोगेटरी एक लिखित अनुरोध है जो एक देश की अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले की जीच में मदद करने के लिए दूसरे देश की अदालत को भेजा जाता है।

फेयरफैक्स ग्रुप के प्रमुख माइकल हर्शमैन 2017 में निजी जासूसों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। वह कई मंचों पर दिखाई दिए और उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले की जांच कांग्रेस सरकार द्वारा पटरी से उतार दी गई थी। हर्शमैन ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ ब्योरा साझा करने के लिए तैयार है। सीबीआई ने अदालत

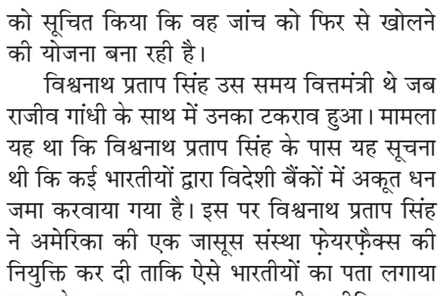

को सूचित किया कि वह जांच को फिर से खोलने की योजना बना रही है।

विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय वित्तमंत्री थे जब राजीव गांधी के साथ में उनका टकराव हुआ। मामला यह था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास यह सूचना थी कि कई भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में अकूत धन जमा करवाया गया है। इस पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमेरिका की एक जासूस संस्था फ़ेयरफ़ैक्स की नियुक्ति कर दी ताकि ऐसे भारतीयों का पता लगाया जा सके। जब यह समाचार भारतीय मीडिया तक पहुँचा तो वह प्रतिदिन इसे सिरमौर बनाकर पेश करने लगा। इस %ब्रेकिंग न्यूज% का उपयोग विपक्ष ने भी खूब किया। उसने जनता तक यह संदेश पहुँचाया कि 60 करोड़ की दलाली में राजीव गांधी की सरकार जांच से भाग रही थी। वीपी सिंह लोगों से कहते थे कि सेना के जवानों ने पहली बार बोफोर्स दागा तो इसने बैक फायर किया और अपने ही कई जवानों की जान ले ली। सिंह ने अपने अंदाज में भरी गर्मी में मोटरसाइकिल पर, गले में गमछा लपेट कर, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह प्रचार किया। वे गांव के लोगों से सरल सा सवाल पूछते थे, क्या आपको अंदाजा है कि राजीव गांधी ने आपके घर में सेंध लगा दी है? फिर वे अपने कुर्ते की जेब से एक माचिस निकालते थे और लोगों को दिखाते थे। इस माचिस को देखो। जब आप अपनी बीड़ी, हुक्का या चूल्हा जलाने के लिए चार आने (25 पैसे) की माचिस खरीदते हैं तो एक चौथाई टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। सरकार इस पैसे से स्कूल। अस्पताल, सड़क और नहर बनती है और सेना के लिए हथियार खरीदती है। यह आपका पैसा है। अगर कोई सेना के लिए हथियार खरीदने के नाम पर इसका कुछ हिस्सा चुरा ले तो क्या यह आपके घर में सेंध लगाना नहीं है? यह बताने के लिए कि केवल राजीव गांधी ने ही यह घूस लिया है, वीपी सिंह एक कहानी सुनाते थे। एक सर्कस में एक शेर था, एक घोड़ा था, एक बैल और एक बिल्ली थी। वे आसपास रहते थे, एक रात किसी ने पिंजड़े खोल दिए और अगली सुबह सर्कस के मालिक को घोड़े और बैल का कंकाल मिला। क्या किसी को शक है कि उन्हें किसने खाया होगा? शेर ने या बिल्ली ने? अगर इतनी बड़ी रकम खाई गई है तो क्या किसी बेचारी बिल्ली ने खाया है? सिर्फ शेर के जैसे राजीव ही खा सकते हैं। केस 2011 में बंद कर दिया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाधी को केस में बरी कर दिया था। उसने एक साल बाद राजनीतिक रूप से सवेदनशील इस मामले में हिंदुजा बंधुओ समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इटली के बिजनेसमैन और कथित तौर पर रिश्वत मामले में बिचौलिए ओत्तावियो क्वात्रोची को 2011 में एक अदालत ने बरी कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआई को अभियोजन वापस लेने की अनुमति दी थी।

बोफोर्स मामले में कब क्या-क्या हुआ?

24 मार्च, 1986: भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1,437 करोड़ रुपये का सौदा हुआ। यह सौदा भारतीय थल सेना को 155 एमएम की 400 होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल, 1987: स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारी को घूस दिए हैं। 60 करोड़ रुपये घूस देने का दावा किया गया। 20 अप्रैल, 1987: लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया था कि न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही बीच में किसी बिचौलिये की भूमिका थी। 6 अगस्त, 1987: रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय कमिटी (जेपीसी) का गठन हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी.शंकरानंद ने किया। फरवरी 1988: मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन पहुंचा। 18 जुलाई, 1989: जेपीसी ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। 26 दिसंबर, 1989: तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी, 1990: सीबीआई ने आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो, कथित बिचौलिये विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ। दिसंबर 1992: मामले में शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। फरवरी 1997: क्वात्रोकी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) और रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई। दिसंबर 2000: क्वात्रोकी को मलयेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह शहर नहीं छोड़ेगा। फरवरी-मार्च 2004: कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और भटनागर को मामले से बरी कर दिया। मलयेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को खारिज कर दिया। अप्रैल 2012: स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है। 13, जुलाई 2013: भारत से फरार हुए क्वात्रोकी की मौत हो गई। तब तक अन्य आरोपी जैसे भटनागर, चड्ढा और आर्डबो की भी मौत हो गई थी। 1 नवंबर, 2018: सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू किए जाने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है।

आज का इतिहास

1877 पहली बार मनुष्य की आवाज रिकॉर्ड हुई, थॉमस एडिसन ने सबसे पहले कहा री हेड अ लिटिल लेम्ब।

1897 लंदन दुनिया का पहला लाइसेंस प्राप्त टैक्सीकैब की मेजबानी का शहर बना।

1907 अमेरिका के मोनोंगह शहर में एक कोयला खदान के विस्फोट में 362 कर्मचारी मारे गए।

1907 जब यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ़ माइन्स की स्थापना हुई, तो पश्चिम वर्जीनिया के मोनोंगा में एक विस्फोट में कम से कम 362 खनिक मारे गए।

1909 रूसी शहर में सेराटोव स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई।

1911 वेस्टर्न यूनियन ने न्यूयॉर्क और लंदन के बीच अपनी ट्रांस-अटलांटिक केबल सेवा के लिए डिस्काउंट दरों की शुरुआत की।

1917 हेलीफैक्स हार्बर, नोवा स्कोटिया, कनाडा में एक जहाज, जो टीएनटी और पिक्रिक एसिड ले रहा था, एक अन्य जहाज के साथ टक्कर के बाद आग लग गई और इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित आकस्मिक विस्फोट हुआ।

1917 फिनलैंड की सीनेट ने आधिकारिक तौर पर रूस में देश की आजादी की घोषणा की।

1921 एंग्लो-आयरिश संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और फिर एक साल बाद बलपूर्वक अस्तित्व में आए, आयरिश फ्री स्टेट की स्थापना, ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाला पहला स्वतंत्र आयरिश राज्य।

1928 संयुक्त राज्य के इशारे पर, कोलम्बियाई सेना ने संयुक्त फल कंपनीवर्कर्स द्वारा एक महीने की लंबी हड़ताल को दबा दिया।

1935 माइकल जोसेफ सैवेज न्यूजीलैंड के 23 वें प्रधान मंत्री बने।

1953 व्लादिमीर नाबोकोव ने अपना विवादास्पद उपन्यास लोलिता पूरा किया, इसे शुरू करने के पांच साल बाद।

1956 मेलबर्न ओलंपिक में, 14 वर्षीय तैराक सैंड्रा मोर्गनबेक ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का खिताब जीता।

1958 इटली में विश्व की सबसे लम्बी और अत्यंत महत्वपूर्ण सुरंग बनाने का काम आरंभ हुआ। इसकी खुदाई का काम 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद 14 अगस्त सन 1964 को पूरा हुआ।

1975 प्रांतीय आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के चार सदस्यों ने मैरीलेबोन, लंदन के बालकोम्ब स्ट्रीट पर एक घर में दो लोगों को बंधक बना लिया और छह दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया।

बुद्धिजीविता बनाम व्यक्ति निर्माण : संघ की दूरगामी दृष्टि

शिवेश प्रताप

हाल ही में आजतक के साहित्यिक मंच पर पत्रकार राहुल देव और कवि नरेश सक्सेना ने एक गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आरएसएस सौ साल से बौद्धिक कर रहा है, किंतु आज तक ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं पैदा कर पाया, जिसका नाम संघ के बाहर कोई जानता हो। यह सवाल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही विचारणीय भी। ऐसा कह इस कवि-पत्रकार द्वय ने अपने वैचारिक दिवालियेपन से समाज का परिचय कराया और यह बताया की ये बेचारे संघ की रीति और नीति से कितने अनभिज्ञ हैं। इन्हें यह समझना चाहिए की वामपंथ की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ख़ालिस बुद्धिजीवी पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है। संघ का उद्देश्य वास्तविक चरित्र-व्यक्ति निर्माण है, न कि बुद्धिजीविता से कुण्ठित भीड़ का सृजन।

संघ न तो व्यक्ति को केवल बुद्धि आधारित जीवन जीने की शिक्षा देता है और न ही ऐसी किसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अपनी प्रार्थना में संघ का स्वयंसेवक सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् कहकर ऐसा शुद्ध शील-चारित्र्य मांगता है जिसके समक्ष सम्पूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाये। संघ का उद्देश्य बुद्धि को बढ़ावा देना नहीं है, संघ विचार को बढ़ावा देता है। विजेत्री च न: संहता कार्यशक्ति कहकर हम विजयशालिनी संघठित कार्यशक्ति के द्वारा परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं यानि राष्ट्र के वैभव को उच्चतम शिखर पर पहुँचाने का सामर्थ्य मांगते हैं। संघ का हर कार्य आत्मभाव, समर्पण और त्याग पर आधारित है। संघ व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण का मंच है। इसका लक्ष्य हर स्वयंसेवक को भारत माता की सेवा के लिए तैयार करना है। संघ के लिए बुद्धिजीविता साध्य नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्रहित में कार्य करने वाले व्यक्तियों को तैयार करने का माध्यम है।

आज के समाज में बुद्धिजीविता को एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि बुद्धिजीविता केवल क्षणिक परिवर्तन ला सकती है। इसके विपरीत, व्यक्ति निर्माण का प्रभाव दीर्घकालिक और समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक होता है। संघ बुद्धिजीविता की अल्पकालिक चमक के बजाय व्यक्ति निर्माण के दीर्घकालिक प्रभाव में विश्वास रखता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इसी व्यक्ति निर्माण की दिशा में पिछले सौ वर्षों से कार्य कर रहा है।

पूर्व राज्यपाल आचार्य विष्णुकान्त शास्त्री जी कहा करते थे की बुद्धिजीवी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि के आधार पर जीविका चलाता हो। जब बुद्धि के आधार पर जीविका चलाने को महिमामंडित किया गया, तब समाज में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुईं। बीते दशकों में यह सत्य भी होता दिखाई दिया है, डॉक्टरों ने मरीजों को केवल पैसा कमाने का साधन मान लिया, शिक्षकों ने कक्षाओं से गायब होकर अर्बन नक्सल बनने का रास्ता चुना और छात्रों ने टुकड़े-टुकड़े गैंग बनाकर समाज में विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

वामपंथी बुद्धिजीविता ने समाज को हिंसा, विभाजन और अशांति के अलावा कुछ नहीं दिया। यह बुद्धिजीविता पूंजीवादी नेक्सस का हिस्सा बनकर समाज को खोखला करती है। वामपंथ ने श्रमिकों को बुद्धिजीवी बनने का सपना दिखाया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता से कानपुर तक औद्योगिक संयंत्र बंद हो गए। श्रमजीवी लोगों को दाने-दाने का मोहताज कर दिया। इस विचारधारा ने परिवार और सामाजिक मूल्यों को कमजोर किया और देशभक्ति व सांस्कृतिक चेतना पर भी आघात किया।

राहुल देव और नरेश सक्सेना को याद दिलाना चाहता हूं कि आज वह जिस बुद्धिजीविता का महिमा मंडन कर रहे हैं इस वामपंथी बुद्धिजीविता के राजनैतिक गढ़ त्रिपुरा को कुछ वर्ष पहले संघ के चार समर्पित स्वयंसेवकों श्री श्यामलकांति सेनगुप्ता, श्री दीनेंद्र डे, श्री सुधामय दत्त तथा श्री शुभंकर चक्रवर्ती ने अपने प्राणोत्सर्ग से उखाड़ फेंका। इन चारों को अपहरण 6 अगस्त 1999 को त्रिपुरा के कंचनपुर के वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास से हुआ था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। आपकी सोने की बनी बुद्धिजीवी लंका को व्यक्तिनिर्माण की पूंछ ही जलाकर भस्म करती है। त्रिपुरा ने व्यक्ति निर्माण से आपकी बुद्धिजीविता को उत्तर दिया, आगे और भी नाम जुड़ेंगे।

वामपंथी और पूंजीवादी नेक्सस आज इतना मजबूत हो चुका है कि पूरी दुनिया इसके प्रभाव में है। राष्ट्र की संकल्पना में बुरु तरह विफल वामपंथी बुद्धिजीविता ने अब अपना रूप बदल समाज में भ्रम फैलाकर परिजीवी के रूप में पूंजीवाद को प्रश्रय दे रहा है। अमेरिका से भारत तक बुद्धिजीविता ने पूंजीवाद की दासी बनकर राजनीति और समाज में अपनी जगह बनाई। भारत से लेकर अमेरिका तक राष्ट्रभाव का उत्थान इन परिजीवियों के लिए संकट के रूप में खड़ा हुआ है इसलिए ये इतने बेचैन हैं।

राहुल देव और नरेश सक्सेना का यह सवाल कि संघ ने कोई बुद्धिजीवी क्यों नहीं पैदा किया? उचित है और इस तरह से वामपंथी गिरोह के हरावल दस्ते के दो बेरोजगार सेनापति आज जब अपने पुराने बुद्धिजीवी अखाड़े में संघ को ललकार रहे हैं तो यह नास्टैल्जिया उनकी बेचारगी को प्रगट कर रहा है। राहुल देव और नरेश सक्सेना जी काश आप इस विषय पर भी विचार करते की जिस देश को तोड़ने के लिए आने वैचारिक पूर्वज लगे रहे और पाकिस्तान बनवाया तो उस पाकिस्तान में आपका बुद्धिजीवी अवशेष क्यों नहीं मिलता?

पुन: एक बार कहना चाहूँगा संघ बुद्धिजीवी पैदा करने का मंच नहीं है। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक यज्ञ है जिसमें सौ वर्षों से अनगिनत प्रचारकों, स्वयंसेवकों नें मैं नहीं, तू ही कह-कह कर स्व जीवन की आहुति दे दिया है। संघ का उद्देश्य व्यक्ति को राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए तैयार करना है। संघ के चरित्रबल और कार्यों ने यह सिद्ध किया है कि समाज का उत्थान बुद्धिजीविता से नहीं, बल्कि नैतिकता और त्याग से होता है। वामपंथी बुद्धिजीविता जहां समाज में विभाजन और अशांति का कारण बनी है, वहीं संघ ने अपने सौ वर्षों के साधना से शांति, समरसता और राष्ट्रभक्ति का दीप जलाया है।

दिव्यांगजनों की सेवा- स्वाभिमान का अमृत दशक

नरेंद्र मोदी

सारा विश्व तीन दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाता है। यह दिव्यांगजनों के साहस, आत्मबल और उपलब्धियों को नमन करने का विशेष अवसर है। भारत के लिए तो यह पवित्र दिन जैसा है। हमारे शास्त्रों और लोक ग्रंथों में दिव्यांगों के प्रति सम्मान का भाव देखने को मिलता है। रामायण में एक श्लोक है-

उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात्परं बलम्।
सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्, न किञ्चिदपि दुर्लभम्।

यानी, जिस व्यक्ति के मन में उत्साह है, उसके लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। दिव्यांगजन इसी उत्साह से देश के सम्मान और स्वाभिमान की ऊर्जा बन रहे हैं। इस वर्ष यह दिन और भी विशेष है क्योंकि इसी साल संविधान के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। समानता और अंत्योदय के लिए काम करने की संविधान की प्रेरणा से बीते 10 वर्षों में हमने दिव्यांगों की उन्नति की मजबूत नींव रखी है। उनके लिए अनेक नीतियां बनीं, अहम निर्णय हुए हैं। मैंने हर मौके पर दिव्यांगजनों का जीवन आसान बनाने के लिए प्रयास किए हैं। पीएम बनने के बाद मैंने इस सेवा को राष्ट्र का संकल्प बनाया। 2014 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित किया। यह सिर्फ शब्द का परिवर्तन नहीं था, इसने समाज में दिव्यांगजनों की गरिमा भी बढ़ाई और उनके योगदान को भी बड़ी स्वीकृति दी। इस निर्णय ने संदेश दिया कि सरकार ऐसा समावेशी वातावरण चाहती है, जहां किसी व्यक्ति के सामने उसकी शारीरिक चुनौतियां दीवार ना बनें और उसे उसकी प्रतिभा के अनुसार पूरे सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण का अवसर मिले। दिव्यांग भाई-बहनों ने विभिन्न अवसरों पर मुझे इस निर्णय के लिए अपना आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद ही, दिव्यांगजन के कल्याण के लिए मेरी सबसे बड़ी शक्ति बना।

पहले की सरकारों के समय जो नीतियां थीं...उनकी वजह से दिव्यांगजन सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के अवसरों से पीछे रह जाते थे। हमने उन स्थितियों को बदला। आरक्षण की व्यवस्था को नया रूप मिला। दिव्यांगजन के कल्याण के लिए खर्च होने वाली राशि को तीन गुना किया गया। इससे दिव्यांगजनों के लिए अवसरों व उन्नतियों के नए रास्ते बने।

जीवन को सरल, सहज और स्वाभिमानी बनाने के भाव के साथ दिव्यांगता कानून को लागू किया गया। पहली बार एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी दिव्यांगता की परिभाषा में शामिल किया गया। यह कानून उनके सशक्त जीवन का माध्यम बन रहा है और वे विकसित भारत के निर्माण के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि उनकी उपलब्धियां कैसे हमारे समाज के संकल्पों को नया आकार दे रही हैं।

आज जब पैरालंपिक का मेडल सीने पर लगाकर, मेरे देश के खिलाड़ी मेरे घर पर पधारते हैं, तो मन गौरव से भर जाता है। जब मैं मन की बात में दिव्यांग भाई-बहनों की प्रेरक कहानियां आपके साथ साझा करता हूं, तो हृदय गर्व से भर जाता है। शिक्षा हो, खेल या फिर स्टार्टअप, वे सभी बाधाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि 2047 में जब हम स्वतंत्रता का 100वां उत्सव मनाएंगे, तो हमारे दिव्यांग साथी पूरे विश्व का प्रेरणा पुंज बने दिखाई देंगे। आज हमें इसी लक्ष्य के लिए संकल्पित होना है।

दूर का सपना है मणिपुर में 'शांति'!

पूनम आई. कौशिश

7 नवंबर: मणिपुर का एक छोटा सा शांत जिरीबाम जिला, जहां पर संदिग्ध कुकी उपद्रवियों द्वारा 3 मैतेई महिलाओं और 3 बच्चों का अपहरण किया जाता है और उसके बाद 1 महिला और 2 बच्चों की हत्या की जाती है तथा उनके शव जिरीबाम नदी में मिलते हैं जिसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन, हत्याएं, आगजनी की घटनाएं होती हैं, भीड़ द्वारा राज्य के कई मंत्रियों और विधायकों के घर जलाए जाते हैं। केन्द्र सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय बलों की 70 कंपनियां भेजता और कर्फ्यू लगाता है। गृह मंत्री शाह अपने महाराष्ट्र के चुनावी दौरे को बीच में ही छोड़कर दिल्ली आते हैं और राज्य के 6 पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा) पुनः लागू कर देते हैं। इस कदम से अविश्वास बढ़ता है और एक तरह से असंभव स्थिति पैदा हो जाती है।

मणिपुर में मुख्यत: हिन्दू मैतेई बहुसंख्यक और ईसाई कुकी समुदाय के बीच 19 माह से जातीय संघर्ष चल रहा है और इसका कारण मैतेई समुदाय द्वारा आरक्षण सहित अनुसूचित जनजाति का दर्जा करने की मांग करना है। कुकी जोमी द्वारा इसका विरोध करने के चलते हुए संघर्ष में 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 60 हजार लोग विस्थापित हो गए। केन्द्रीय बलों द्वारा दोनों समुदायों के बीच शांति स्थापित करने और उपद्रवी तत्वों पर अंकुश लगाने का कार्य किया गया है, किंतु मणिपुर पुलिस द्वारा उनके कार्यों में अड़चनें पैदा की गईं और उन्हें समस्या के अंग के रूप में देखा जाता है। केन्द्र ने वर्ष 2008 में मुख्यत: पहाड़ी क्षेत्रों के 25 उपद्रवी गुटों के साथ कार्रवाई निलंबन समझौता किया था और वह इस समझौते को बनाए रखने के लिए बाध्य है ताकि उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई से जो लाभ मिले, उसे संचित किया जा सके और जमीनी स्तर पर स्थिति और जटिल न बने।

समस्या को एक बात और बढ़ाती है कि दोनों पक्षों के गुटों ने अपने आपको ग्राम रक्षा स्वयंसेवी के रूप में संगठित कर लिया है। पुलिस पर्वतीय क्षेत्रों के स्वयंसेवियों को आतंकवादी कह रही है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के गुट घाटी के लोगों को क्रांतिकारी कह रहे हैं। सबसे दुखद तथ्य

यह है कि राज्य सरकार की कार्रवाई केवल खोखली बातों, बाहरी लोगों को दोष देने, इंटरनैट पर प्रतिबंध लगाने और बातचीत के वायदे करने तक सीमित रह गई है। केन्द्र द्वारा दोनों पक्षों को वार्ता के लिए सहमत कराने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। इसके साथ ही पिछले वर्ष सुरक्षा बलों से जिन 5000 हथियारों को लूटा गया था, वे अभी भी गायब हैं। राज्य सरकार अभी भी इस समस्या को काननू-व्यवस्था की दृष्टि से देखती है। उसके संकीर्ण दृष्टिकोण से सुरक्षा बलों की कठिनाइयां बढ़ी हैं और पड़ोसी बंगलादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते स्थिति और उलझी है।

मणिपुर आज मौत की घाटी के रूप में बदल रहा है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए केन्द्र ने क्या कदम उठाए हैं? या केन्द्र अभी तक केवल बातें और फोटो ड्क्षखचवाने तक सीमित है। साइन बोर्डों पर सामाजिक पहचान लिखी जा रही है, फिर भाईचारे के संवैधानिक सिद्धान्त का क्या हुआ? दुर्भाग्यवश सभी पार्टियां इस स्थिति का दोहन कर रही हैं। किंतु सब लोग इस बात से सहमत हैं कि मणिपुर में जो संघर्ष और खून-खराबा चल रहा है, वह बीरेन सिंह द्वारा अपनी कुर्सी बचाने का एक राजनीतिक खेल है। वह 2 दशक से राजनीति में हैं और मैतियों के एक बड़े नेता हैं तथा उनका झुकाव हिन्दुत्व की ओर है। उनका एजैंडा है कि अपने समुदाय के लिए अधिकतम राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए जाएं, जो अपने हिन्दुत्व ब्रांड के माध्यम से केन्द्र से अपने कार्य करवाएं।

असम के मुख्यमंत्री हिमन्ता बिस्व सरमा, जो नार्थ ईस्ट डैमोक्रेटिक अलायंस के प्रमुख हैं और वर्तमान में हिन्दुत्व के पोस्टर ब्वॉय हैं, का कहना है कि मणिपुर में जनसंख्या का वितरण इस तरह है कि 70 प्रतिशत लोगों के पास 30 प्रतिशत भूमि है। कुकी और नागा घाटी में आ सकते हैं किंतु मैतेई पहाड़ों पर नहीं जा सकते। यही स्थिति बोडोलैंड के बारे में असम में भी है। पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे ने कहा कि मणिपुर में विदेशी हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चीन कई वर्षों से मणिपुर में विभिन्न उपद्रवी समूहों की सहायता कर रहा है और इसके अलावा सीमा पार मादक द्रव्यों का व्यापार खूब फल-फूल रहा है। फिर आगे की रूपरेखा क्या है? कुछ भी नहीं। केन्द्र द्वारा गठित शांति समिति विफल हो गई है क्योंकि कुकी और मैतेई दोनों समूहों का कहना है कि वे इसकी बैठकों में भाग नहीं लेंगे। अब तक इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस प्रकार इस स्थिति का समाधान करेगी। लगता है इस बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इससे यह मामला और उलझा है।

केन्द्र और राज्य दोनों को यह स्वीकार करना होगा कि चर्चा और बहस में बढ़त से टी.वी. एंकरों को लाभ मिलेगा किंतु इससे समस्या और जटिल होगी तथा मणिपुर के घावों पर और नमक छिड़का जाएगा जो अच्छा नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतें और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक तंत्र बनाया जाए। यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्य सरकार राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता का निराकरण करें और अफस्पा जैसे उपाय न अपनाएं। केन्द्र को बीरेन सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह कानून के शासन को स्थापित करे और प्रशासन को पटरी पर लाए तथा लोगों के घावों पर मरहम लगाए। निस्संदेह हमारा राजनीतिक नेतृत्व विफल हुआ है। हर कोई पानी पर लकीर खींचने और राजनीतिक बढ़त लेने का प्रयास कर रहा है और संसद भी इस मुद्दे का समाधान ढूंढने में विफल रही है क्योंकि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल इस टकराव को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए सहमत नहीं हैं। हमारे नेताओं को सामूहिक रूप से मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच पैदा हुई खाई को पाटने के लिए उपायों पर विचार करना चाहिए क्योंकि मणिपुर की अशांति का प्रभाव पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ता है, जैसा कि मिजोरम में देखने को मिला है जहां पर एक स्थानीय गुट ने वहां स्थित मैतेई जनसंख्या को धमकी दी है।

राहुल गांधी के लिए कठिन है आगे की राह?

हरीश गुप्ता

हरियाणा और महाराष्ट्र में लगातार दो शर्मनाक पराजय के बाद राहुल गांधी के लिए चिंतित होने की वजहें हैं। कांग्रेस को फरवरी 2025 की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोई उम्मीद नहीं है। जून 2024 में लोकसभा में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी सातवें आसमान पर थी। उसने हरियाणा में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उम्मीद थी कि यह व्यवस्था आने वाले सालों में भी जारी रहेगी। लेकिन कांग्रेस अनिच्छुक हो गई और अब आप के अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हो सकता है कि महाराष्ट्र में हार के बाद बदले राजनीतिक माहौल में 'सीटों के तालमेल' की गुंजाइश हो।

ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली में फिर से उभर रही भाजपा बाजी पलट सकती है, जहां केजरीवाल को 40 करोड़ रुपए का 'शीश महल' (नया सीएम बंगला) महंगा पड़ा है। कांग्रेस जानती है कि बिहार में भी उसका कोई मजबूत आधार नहीं है और वह राजद पर निर्भर है, जो अपनी कानूनी समस्याओं से जूझ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में होने हैं और एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रहा है।

भाजपा ने राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ समझौता कर लिया है। इन सब बातों ने राहुल गांधी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है क्योंकि मार्च 2026 में असम में कांग्रेस का आमना-सामना भाजपा से होने वाला है। असम में कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्यम स्तर के नेता चिंतित हैं क्योंकि पार्टी को भाजपा के खिलाफ इसी तरह का हश्र झेलना पड़ सकता है।

कहा जा रहा है कि असम कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह और राहुल गांधी द्वारा समय रहते जीत की रणनीति तैयार न कर पाना पार्टी के राज्य में जीत न पाने की कुछ वजहें हो सकती हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और केरल में कांग्रेस भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में शामिल नहीं है। इन राज्यों में भी अप्रैल-मई 2026 में चुनाव होने हैं।

अगले भाजपा अध्यक्ष के लिए दो प्रमुख शर्तें

महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न होने के साथ, अब भाजपा वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्थान पर अपने नए अध्यक्ष

का चुनाव करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा के नेता भी हैं। पूरी संभावना है कि अगले दो महीनों के भीतर नए भाजपा प्रमुख द्वारा पदभार संभाल लिया जाएगा। 'संघ परिवार' के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अगले भाजपा प्रमुख को दो प्रमुख मानदंडों को पूरा करना होगा।

पहला यह कि वह एक पक्का आरएसएस स्वयंसेवक होना चाहिए। दूसरा यह कि उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वासपात्र भी होना चाहिए। पार्टी के सुचारु संचालन और सरकार के साथ समन्वय के लिए यह आवश्यक है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के बहुमत खोने के बाद आरएसएस की आवाज महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए नड्डा के उत्तराधिकारी को चुनने में कुछ देरी हुई है।

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद कुछ नेताओं का ग्राफ आसमान छू गया है, जैसे; केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, जो क्रमश: महाराष्ट्र और हरियाणा के प्रभारी थे। हालांकि मोदी के एक और चहेते अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री, यादव के साथ रणनीति बनाने का हिस्सा थे, लेकिन पार्टी में अपेक्षाकृत नए होने के कारण वे दौड़ में नहीं हैं।

दिलचस्प बात यह है कि यादव और वैष्णव की जोड़ी ने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में, भाजपा ने सभी 29 लोकसभा सीटें भी जीतीं। यह अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान, जो भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे ऊपर थे, झारखंड में हार के बाद पिछड़ गए। उन्हें झटका तब लगा जब भाजपा ने झारखंड खो दिया, हालांकि वे राज्य विधानसभा चुनावों के लिए हिमंत बिस्वा सरमा के साथ प्रभारी थे। इस बात की भी काफी अटकलें हैं कि दक्षिण से कोई नेता उनकी जगह ले सकता है।

बिहार में एक और नेता-पुत्र का होगा उभार !

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरती सेहत के मद्देनजर चिंतित जनता दल (यू) के नेताओं ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। पार्टी में कोई स्वीकार्य दूसरा व्यक्ति न होने के कारण पार्टी को एकजुट रखने के लिए खोज तेज कर दी गई है। पटना में इस बात की जोरदार अफवाह है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए अत्यधिक दबाव में हैं, जो एक बड़ी दुविधा का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे हमेशा राजनीति में 'परिवारवाद' के खिलाफ रहे हैं।

निशांत, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) मेसरा के पूर्व छात्र हैं, चकाचौंध और राजनीतिक आयोजनों से दूर रहते हैं। 49 वर्षीय निशांत ने कुछ समय पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने अध्यात्म का मार्ग चुना है और उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है।

उन्होंने बाजार में देखे जाने पर अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की और कहा कि वे एक ऑडियो सेट खरीदने आए थे क्योंकि वे अपने मोबाइल फोन पर 'हरे रामा हरे कृष्णा' सुनना चाहते थे, जिसकी आवाज कम है। जब भी वे पटना की सड़कों पर निकलते हैं, तो सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ होते हैं।

कुछ समय पहले उन्हें स्थानीय इलाके में एक पौधा लगाते हुए भी देखा गया था। दिग्गज राजनेता के बेटे के उत्थान पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन जद (यू) के पास भी विकल्प नहीं हैं। नीतीश कुमार ने पहले जिसे भी अपना संकटमोचक प्रभारी बताया था, उसके साथ लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए; चाहे वह आरसीपी सिंह हों या अन्य।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी के नए चहेते और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे को लाने की मांग के पीछे का उद्देश्य किसी भी आकस्मिक घटना की स्थिति में बागडोर संभालने की आकांक्षा रखने वाले अन्य नेताओं की संभावना को दूर करना है। अगले वर्ष 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा के मुद्दे पर क्यों इतने हमलावर हुए केजरीवाल?

अभिषेक दीक्षित

अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अचानक बेहद हमलावर हो उठे हैं। वे रोज-रोज दिल्ली में हो रहे अपराध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तो लगातार आपराधिक घटनाएं घटती रही हैं। ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी ने अचानक सुरक्षा के मुद्दे पर हमलावर रुख क्यों अपनाया? केजरीवाल की रणनीति में इस बदलाव का क्या असर होगा। भाजपा इसके जवाब में क्या रणनीति अपना सकती है? केजरीवाल दिल्ली में हो रहे अपराध को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा से सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर उन्होंने कई ट्वीट कर भाजपा को घेरने का काम किया है। दिल्ली का नक्शा दिखाते हुए उसमें अलग-अलग जगहों पर हुई अपराध की घटनाओं को दिखाते हुए उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। विधानसभा के पटल से भी उन्होंने इस विषय की गंभीरता को उठाया। संजय सिंह ने इस मामले को संसद में चर्चा के लिए भी लाने की मांग की। संसद भवन के परिसर में भी उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान सुरक्षा के मुद्दे पर खींचा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस समय गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। तथाकथित शराब घोटाले और मुख्यमंत्री के आवास में भारी खर्च कर ऐशोआराम की वस्तुएं लाने की खबरों ने केजरीवाल की उस छवि को बहुत धक्का पहुंचाया है जिसने आम जनता के बीच उनकी छवि एक ईमानदार, साफ-स्वच्छ छवि का व्यक्ति और जनता के लिए काम करने वाले नेता की बनाई थी। चुनाव के समय पुराने मुद्दे कितने ही कारगर क्यों न हों, बार-बार नहीं चलते। समय के साथ हर चुनाव में राजनीतिक दलों को एक नए मुद्दे के साथ जनता को आकर्षित करना होता है। केजरीवाल की मुफ्त बिजली-पानी और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की योजनाएं आकर्षक हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी वोट खींचने की चमक कमजोर पड़ी है। ऐसे में केजरीवाल के पास नया मुद्दा चाहिए। नए मुद्दे के रूप में सुरक्षा एक आकर्षक विषय हो सकता है जो आम जनता को उनसे जोड़ने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि केजरीवाल ने एक रणनीति के तहत सुरक्षा को अपना पहला मुद्दा बना लिया है। भाजपा भी केजरीवाल की इस रणनीति को समझ रही है। यही कारण है कि समय रहते उसने केजरीवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल सुरक्षा के मुद्दे को उठाकर %शराब घोटाले% और %शीश महल विवाद% से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन यह संभव नहीं होगा। जनता जानती है कि केजरीवाल इसी तरह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नए-नए मुद्दों के पीछे छिपने का काम करते हैं। केजरीवाल की रणनीति को भांपते हुए भाजपा एक आक्रामक अभियान चलाकर उनके भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता के सामने लाने की तैयारी भी कर रही है। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में एक पूर्व मुख्यमंत्री पर हुए जानलेवा हमले का मुद्दा सामने आ जाने से भाजपा को हमलावर होने का अवसर मिल गया। पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में एक पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दिल्ली की सुरक्षा का मामला उठा रहे हैं। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि नरेश बाल्यान और नरेश यादव के मामले के कारण भी केजरीवाल का सुरक्षा को मुद्दा बनाने का दावा कमजोर पड़ा है। यदि ऐसा कोई भी विवाद सामने आया तो केजरीवाल इस बेहतरीन मुद्दे की धार खो सकते हैं।

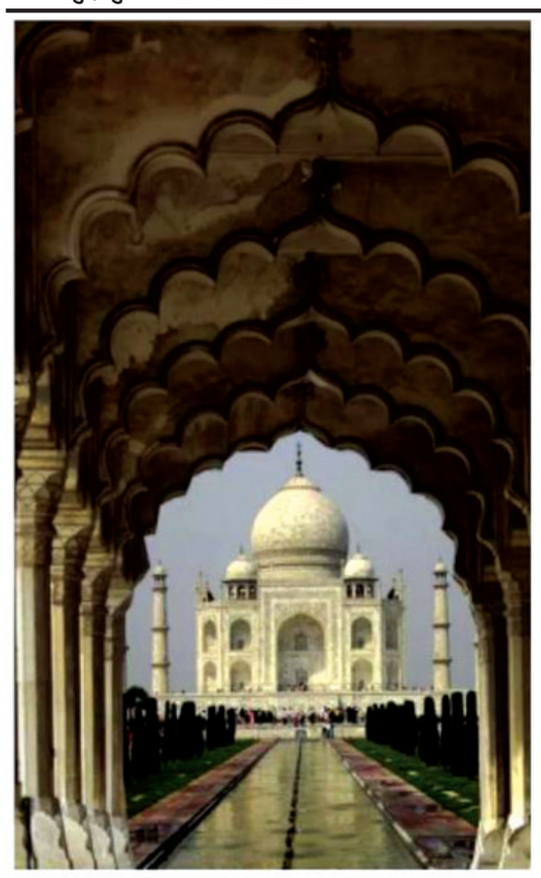

अगर आपने ताजमहल नहीं देखा तो अब देर न करिए

ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं और अगर आप भारत में रहकर भी अब तक ताजमहल नहीं देख पाए हैं तो अब और देर न करिए। जितनी जल्दी हो सके जाएं और देखकर आएं, इस ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती ने दुनियाभर के लोगों को अपना दीवाना बनाकर रखा है। इससे पहले की आप ताजमहल घूमने का प्लान बनाएं, हम यहां आपको इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देना चाहते हैं, जिससे की आपकी यह यात्रा बिना किसी परेशानी बिल्कुल आराम से बीते...

ताजमहल कैसे पहुंचें?

आगरा भारत का एक प्रमुख शहर है। इसलिए हवाई मार्ग हो या रेल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग। आगरा भारत वर्ष के सभी प्रमुख शहरों से सभी मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ा है।

हवाई मार्ग

अगर आप हवाई मार्ग द्वारा आगरा जा रहे है तो आगरा का पंडित दीनदयाल उपध्याय हवाई अड्डा ताज महल से 16 किमी की दूरी पर स्थित है। यहां से आप आसानी से टैक्सी या आटो द्वारा आसानी से ताजमहल पहुंच सकते है। महानगर होने के नाते यहा काफी ट्रैफिक रहता है। जिसके कारण आपको आगरा एयर पोर्ट से ताजमहल पहुंचने में लगभग 40 मिनट लग सकते हैं, अगर ट्रैफिक न हो तो यह मार्ग सिर्फ 20-25 मिनट का है।

रेल मार्ग

यदि आप रेल मार्ग द्वारा आगरा जा रहे हैं तो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी लगभग 2.5 किमी है। रेलवे स्टेशन से ताजमहल के लिए ऑटो और रिक्शा वालो की काफी भीड़ लगी रहती है। अगर आपके पास भारी लगेज नहीं है तो आप आगरा के किले का बाहरी भाग के दर्शन करते हुए किले के सामने से होते हुए शिवाजी चौक से ताजमहल पहुंच सकते हैं। शिवाजी चौक से ताजमहल का सेप्रेट रास्ता गया है, जो पश्चिमी गेट पर जाता है। कार, टैक्सी या ऑटो से आने वाले यात्री भी इसी मार्ग से जाते हैं। इसी सेपरेट मार्ग पर कुछ दूरी पर ताजमहल कार पार्किंग है।

सड़क मार्ग

अगर आप कार द्वारा दिल्ली से आगरा जा रहे हैं तो नोयडा आगरा एक्सप्रेस वे से जा सकते हैं। यह सुविधाजनक एवं फास्टेट रूट है। इसके आलावा आप दिल्ली से मथुरा होते हुए पुराने हाइवे से भी आगरा पहुंच सकते हैं।

कार पार्किंग

ताजमहल कार पार्किंग से ताजमहल की दूरी लगभग 700-800 मीटर है। आप चाहे एयर पोर्ट से टैक्सी से जाएं या रेलवे स्टेशन से ऑटो से जाएं या फिर अपनी कार से जाएं पहुंचना आपको कार पार्किंग में ही है। कार पार्किंग पर पहुंचते ही आपको ऊंट गाड़ी और बैट्री गाड़ी वाले घेर लेंगे, क्योंकि कार पार्किंग से ताजमहल के बीच की इस दूरी में बैट्री गाड़ियां व ऊंट गाड़ियां चलती हैं, जो बीस से तीस रुपए प्रति सवारी लेते हैं। कार पार्किंग से आगे किसी भी तरह के प्राइवेट वाहनों के जाने की अनुमति नहीं होती है। आप कार पार्किंग से ताजमहल गेट तक पैदल भी जा सकते है। 700 मीटर की दूरी कोई ज्यादा नही होती है।

अमानती घर

मार्ग के रास्ते में स्थित अमानती घर में आप अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि ताजमहल के अंदर किसी भी प्रकार का अटैची, बेग (हैंड बेग को छोड़कर) किसी भी तरह का खाने-पीने का सामान खाना, बिस्कुट, चिप्स, पान, बीड़ी, सिगरेट (पानी की बोतल को छोड़कर) किसी भी तरह का हथियार चाकू व नशीले पदार्थ आदि अंदर ले जाना मना है। मोबाइल और कैमरा ले जा सकते है। बाकी आपके पास जो सामान है, उसे आप अमानती घर में सुरक्षित रख सकते हैं।

शूज कवर

यही टिकट खिड़की के पास ही आपको शूज कवर बेचने वाले भी मिल जाएंगे। उनसे आप बीस रुपए देकर शूज कवर खरीद लें, क्योंकि ताजमहल के संगमरमर के चबूतरे पर जूते-चप्पल लेकर जाना मना है। वही टिकट खिड़की के पास आपको गाइड और फोटोग्राफर घेर लेंगे, जो आपको कई तरह के प्रलोभन भी देंगे (जैसे - सॉटकट से अंदर ले जाना का) क्योंकि एंट्री गेट पर चैकिंग प्वाइंट पर काफी लंबी कतार होती है या तो आप उनसे सही एवं पहले ही मोल-भाव कर तय कर लें या फिर टिकट कांटर से पर्यटन विभाग द्वारा गाइड हायर कर सकते हैं। चैकिंग प्वाइंट पर महिला, पुरुष व विदेशियों की अलग-अलग लाइनें होती हैं। यहां ज्यादा समय नही लगता 20-25 मिनट में आप अंदर पहुंच सकते हैं।

अलग-अलग प्रवेश द्वार

ताजमहल में एंट्री करने के लिए तीन गेट्स हैं, जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में मौदूद हैं। इन तीनों गेट्स में जिस गेट पर लोगों की भीड़ सबसे कम होती है वह है इसका पश्चिमी गेट। इस गेट से आप आसानी से ताजमहल के परिसर में एंट्री कर सकते हैं।

शुक्रवार को न जाएं ताजमहल

आमतौर पर ताजमहल रोजाना सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन शुक्रवार को इसे नमाज के लिए बंद रखा जाता है। पूर्णमासी के दिन ताजमहल के गेट्स रात 8.30 बजे से 12.30 बजे तक खुले रहते हैं। चांद की रोशनी में ताजमहल बेहद खूबसूरत लगता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि रमजान के पवित्र महीने में आप रात के वक्त ताजमहल का दीदार नहीं कर सकते।

आगरा घूमने आए हैं तो ताजमहल को लास्ट में देखें

यहां हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप ताजमहल के टिकट पर थोड़ा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आगरा में दो-तीन दिन के लिए हैं तो ताजमहल घूमने का प्लान अपनी यात्रा के आखिरी दिन रखिए। दरअसल अगर आगरा के किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे आगरा फोर्ट से ताजमहल की टिकट खरीदते हैं तो आपको इस पर कुछ छूट मिल सकती है। यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जारी किए गए टिकट पर उसी दिन का स्टैंप हो जिस दिन आपको ताजमहल जाना है।

अलग लोगों के लिए अलग कीमत

अगर आप भारतीय हैं तो आपको ताजमहल देखने के लिए 50 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ेगी। 15 साल से कम के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट का दाम 1100 रुपए है। आप इन टिकटों को एक दिन अडवांस में सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस से ले सकते हैं।

क्या लेकर नहीं जा सकते ?

सुरक्षा कारणों से कुछ ऐसी चीजे हैं, जिनके साथ आप ताजमहल के अंदर नहीं जा सकते। ट्राईपॉड, मोबाइल फोन चार्जर, खाने-पीने की वस्तुएं व तंबाकू जैसी चीजें यहां बैन है। हालांकि यहां एक लॉकर रूम है, जहां आप अपने सामान को सुरक्षित तरीके से जमा कर सकते हैं और वापस लौटने पर यहां से अपने सामान को ले सकते हैं।

यह है बेस्ट सीजन

अगर मुमकिन हो तो ठंड के मौसम में ताजमहल घूमने का प्लान न बनाएं, क्योंकि कोहरे के कारण इसकी खूबसूरती खिल के बाहर नहीं आती। ताजमहल घूमने का बेस्ट सीजन होता है मार्च से जून। अगर आप ताजमहल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बस ऊपर बताई गई इन टिप्स का ध्यान रखें और अपनी ताज यात्रा को यादगार बनाएं।

ताजमहल के बारे में रोचक बातें, जो आपको नहीं होंगी पता

ताजमहल मुगल वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। मोहब्बत की इस निशानी को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था। दुनियाभर से करोड़ों की संख्या में पर्यटक ताजहमल देखने के लिए आगरा आते हैं। हर प्रेमी जोड़े की ख्वाहिश होती है कि वह ताजमहल जाकर अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीर खिंचवाए। इश्क की इस निशानी को निहारे, संगमरमर की इमारत की खूबसूरती को अपनी स्मृतियों में कैद कर लें। आइए आपको ताजमहल के बारे में 10 रोचक बातें बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।

- ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे थे।
- 22,000 से ज्यादा मजदूरों ने ताजमहल के निर्माण में काम किया था।
- 1,000 हाथियों के जरिए ताजमहल के निर्माण सामग्री को लाया गया था।
- ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था।
- ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था।
- 28 तरह के रत्नों को श्रीलंका से लेकर चीन और भारत के विभिन्न राज्यों से लाया गया था।
- संगमरमर के सफेद पत्थर को राजस्थान से लाया गया था।
- तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना, पंजाब से जैस्पर और क्रिस्टल को चीन से मंगाया गया था।
- ताजमहल की वास्तु शैली में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है।
- ताजमहल का निर्माण 1632 ईश्वी में शुरू हुआ था और 1653 में गुम्बद बनकर तैयार हुआ।
- अगर आप भी मुहब्बत की इस सबसे विश्व प्रसिद्ध निशानी को देखना चाहते हैं तो ताजमहल जरूर जाएं।
- आप दिल्ली में रहते हैं तो सिर्फ ताज एक्सप्रेस हाईवे से सिर्फ साढ़े तीन घंटे में आगरा पहुंच सकते हैं।

बड़ी अद्भुत है ताजमहल के निर्माण की कहानी

यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल आज न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहां आते हैं। प्यार का प्रतीक माने जाने वाले ताजमहल की खूबसूरती जितनी चर्चा में रहती है, उतनी ही इसके बनने की कहानियां चर्चा में रहती हैं। ताजमहल को बनाने को लेकर अलग-अलग मिथ हैं। कहा जाता है कि मुमताज की याद में बनायी गई इस खूबसूरत इमारत जैसी कोई और इमारत न बने, इसलिए शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल को बनाने में करीब 20 हजार मजदूरों ने योगदान दिया था। और इसका काम करीब 22 साल तक चला।

हालांकि कारीगरों के हाथ कटवाने की एक और भी कहानी बताई जाती है। माना जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उनसे ताउम्र काम न करने का वादा लिया था, जिसके बदले में उन्हें जिंदगी भर वेतन दिया गया था। वहीं एक मिथक ये भी है कि शाहजहां ने ताजमहल ख्वाब में देखकर बनवाया था, लेकिन ताजमहल के नक्शे के हिसाब से इतिहासकारों की मानें तो इसके डिजाइन के लिए पूरी दुनिया के वास्तुशास्त्रों की मदद ली गई थी, लेकिन इसका सटीक डिजाइन किसने तैयार किया था, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। ताजमहल को लेकर ऐसे ही कई मिथक हैं जिनके बारे में कई तरह की कहानियां कही जाती हैं। बता दें कि ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मजार है। मुमताज के

गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहन बनावाया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनवाया गया है। इसके चार कोनों में चार मीनारे हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत चीज को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया, जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था।

इसी तरह बुखारा शहर से कारीगर को बुलवाया गया था, वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वहीं गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तम्बुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया और मिनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया था और इस तरह अलग-अलग जगह से आए करीगरों ने ताजमहल बनाया था।

आगरा के अन्य दर्शनीय स्थल

आगरा में ताजमहल के अलावा अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जो बरबस यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनमें प्रमुख हैं-

आगरा का लाल किलाः जिस स्थान पर आगरा का किला स्थित है, बहुत समय पहले यहां बादलगढ़ का किला हुआ करता था। हालांकि समय के साथ-साथ वह किला नष्ट हो गया था। मुगल सम्राट अकबर ने 1563 ई. से 1573 ईस्वी तक लगभग 8 वर्षों में बादलगढ किले के ध्वंस अवशेषों पर इस किले का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट अकबर ने इस किले में अकबरी महल, जहांगीरी महल, प्राचीर तथा प्रवेश द्वार अकबर ने बनवाए थे, जबकि शीश महल, खास महल, दीवाने आम और दीवाने खास तक मोती मस्जिद का निर्माण अकबर के पोते सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इस किले में दिल्ली दरवाजा, अमरसिंह दरवाजा, दरियाई दरवाजा तथा दर्शनी दरवाजा नामक चार दरवाजे हैं। पर्यटको के लिए प्रवेश द्वार के रूप में अमर सिंह दरवाजा ही खुला होता है। किले के अंदर तीन मस्जिदें भी है – मीना मस्जिद, शाही मस्जिद और नगीना मस्जिद जो दर्शनीय है।

रामबागः यह बाग अपनी हरियाली और सुंदरता से यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाबर द्वारा बनाए गए इस बाग के बारे में कहा जाता है कि यह भारत का पहला मुगल उद्यान था। इस बाग के सौंदर्य को पास बहती यमुना नदी और भी मनमोहक बना देती है।

प्यार की निशानी ताजमहल की ये 5 बातें आपको कर देंगी हैरान

ताजमहल, उसकी खूबसूरती और उससे जुड़ी खूबसूरत यादों के बारे में सभी बातें करते हैं। मगर इस धरोहर के बारे में जितना सुनों उतना कम ही लगता है, परंतु इसमें से कुछ हकीकत और कुछ फसाना भी हैं। हम यहां आपको ताजमहल से जुड़ी ऐसी 5 बातें बता रहे हैं, जो संभवतः आप नहीं जानते होंगे-

आगरा में नहीं बनना था ताजमहल

ताजमहल का निर्माण आगरा में नहीं होने वाला था, मुमताज महल जिसके लिए ताजमहल बनवाया गया था, उनकी मौत दरअसल आगरा में हुई ही नहीं थी, उनकी मौत बुरहानपुर में हुआ था, जो आज के समय में मध्य प्रदेश में है। शाहजहां ने ताज महल के लिए बुरहानपुर में ताप्ती नदी के ठीक किनारे एक जगह पसंद की थी, लेकिन बुरहानपुर में जरूरत के अनुसार सफेद मार्बल नहीं पहुंच सके, इसलिए बाद में ताजमहल आगरा में बनाने का फैसला किया गया। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे आज भी वह जगह विरान पड़ी है।

क्या सच है कि काला ताजमहल भी होता ?:

ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के किनारे काले संगमरमर में ताजमहल की प्रतिकृति बनाना चाहते थे। शाहजहां को यह विचार जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर नाम के एक यूरोपीय यात्री ने दिया था, जो 1665 में आगरा में था। दावा यह भी किया जाता है कि औरंगजेब के कारण शाहजहां की योजना पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। यमुना नदी से लगे महताब बाग में कुछ काले मार्बल देखे भी गए थे, लेकिन बाद में जांच परख के बाद इतिहासकारों और आर्कलॉजिस्ट सोसाइटी ने इस बात का खुलासा किया कि दरअसल महताब बाग में मिले काले मार्बल गंदगी के कारण काले पड़ गए हैं। वह मूल रूप से सफेद ही थे, इसलिए यह बात अफवाह से कम नहीं कि शाहजहां काले ताजमहल भी बनवाना चाहता था।

क्या सचमुच कारीगरों के हाथ काटे गए थे?

ताजमहल के बारे में यह कहा जाता है कि उसने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे और कुछ को मार भी दिया था, लेकिन इतिहास में कहीं भी इस बात का साक्ष्य नहीं पाया गया।

ताजमहल को उजाड़ना चाहते थे अंग्रेज?

ताजमहल से जुड़ी कहानियों में एक नाम और आता है, भारत के गर्वनर जनरल लॉर्ड विलियम बेनटिंक का। कहा जाता है कि लॉर्ड ताजमहल को गिराना चाहता था और उसके मार्बल की नीलामी करना चाहता था। इस बात के भी कहीं सबूत नहीं पाए गए। हालांकि उसके बायोग्राफर जॉन रोसेली ने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि आगरा फोर्ट को बनाने के बाद बचे हुए मार्बल्स को लॉर्ड ने नीलाम कर दिया था।

ताजमहल में लगा है एक लैंप

ताजमहल में एक लैंप लगा हुआ है। कहा जाता है कि इसे बनाने में दो वर्ष का वक्त लगा था। इसे खास ताजमहल की नक्काशी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। इसे मिश्र के कुछ कलाकार और टोड्रोस बदीर नाम के आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया था।

ताजमहल के रहस्य

- आपको यह जानकर हैरानी होगी की ताजमहल का आधार (नीव) लकड़ी पर टिकी है। इस लकड़ी की खासियत यह है कि यह लकड़ी जितनी पानी में रहती है, उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। यमुना नदी का पानी आज भी इस लकड़ी को मजबूत करता है।
- ताजमहल की छत में एक छेद है, जिसमें से बरसात के समय आज भी पानी टपकता है। इसके बारे में एक दंतकथा प्रचलित है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद सभी कारीगरों के हाथ कटवाने का ऐलान कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां चाहते थे कि ऐसी खूबसूरत इमारत दोबारा न बनाई जा सके। शाहजहां के इस फैसले से कारीगर नाराज हो गए, जिसके फलस्वरूप कारीगरों ने जानबूझकर ताजमहल के गुंबद में एक छेद छोड़ दिया था। हालांकि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है। ताजमहल का इतिहास में बस यह एक प्रचलित कथा है।
- सन् 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया।
- ताजमहल का इतिहास का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि ताजमहल दुनिया के सात अजूबो में शामिल है।
- ताजमहल में लगे फव्वारे किसी भी पाइप लाईन से नहीं जुड़े हैं। बल्कि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है, जो सभी एक ही समय पर भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ सभी फव्वारे चल जाते हैं।
- ताजमहल वर्ल्ड में एक दिन में सबसे ज्यादा देखी जानी वाली इमारत है। ताजमहल को एक दिन में लगभग 12000 सैलानी देखते हैं।
- ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया है।
- ताजमल की चारो मीनारें एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं।
- शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो उसने कहा कि ये सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगा, बल्कि उन सबको दोष मुक्त भी करेगा, जो इस पाक जमीं पर अपने कदम रखेंगे और चांद सितारे इसकी गवाही देंगे।
- द्वितीय विश्व युद्ध 1971 भारत-पाक युद्ध के समय इस भव्य इमारत को सुरक्षा की दृष्टि से ताजमहल के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया गया था।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के जज

नईदिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति मनमोहन की नियुक्ति के साथ, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यात्मक शक्ति अब 34 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 33 न्यायाधीशों तक बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को न्यायमूर्ति मनमोहन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय और अभय एस ओका के कॉलेजियम ने बैठक में निर्णय लिया। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया जस्टिस मनमोहन नाम की सिफारिश करते समय, कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि, वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच का प्रतिनिधित्व दिल्ली उच्च न्यायालय के केवल एक न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

झारखंड कैबिनेट का विस्तार 11 मंत्रियों ने ली शपथ

रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिपरिषद ने शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने महेशपुर से झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलायी। 28 नवंबर को सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झामुमो के वरिष्ठ विधायक मरांडी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। मरांडी के शपथ के बाद कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन (जेएमएम) और कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह ने पिछले कैबिनेट पदों को बरकरार रखा। झामुमो ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 34 सीटें जीतीं, जो विधानसभा चुनावों में पार्टी द्वारा प्राप्त अब तक की सबसे अधिक सीटें हैं। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को 16, राजद को 4 और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन को 2 सीटें मिलीं। भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, 21 जीती।

पूर्व विधायक जितेन्द्र सिंह शंटी ने थामा आप का दामन

नईदिल्ली। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जीतेंद्र सिंह शंटी गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। संयोग से, उनकी ज्वाइनिंग राम निवास गोयल की सेवानिवृत्ति के ठीक एक घंटे बाद हुई है। जितेंद्र सिंह शंटी को 2013 में भारतीय जनता पार्टी से शाहदरा से विधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। वह शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक हैं, एक गैर सरकारी संगठन जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने और हिंदू के मार्गदर्शन के अनुसार राख को विसर्जित करने में मदद करता है। शंटी का स्वागत करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें एम्बुलेंस मैन के रूप में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने 70,000 से अधिक शवों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार कराया है। कोविड काल के दौरान, जब लोग ऐसा करने से झिझकते थे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के शवों को स्वीकार किया और उनका अंतिम संस्कार किया।

भाजपा की योजना राजस्व बढ़ाने से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने की

लखनऊ। जीएसटी परिषद द्वारा कई वस्तुओं पर कर बढ़ाए जाने की संभावना की खबरों को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र पर प्रहार करते हुए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की योजना राजस्व बढ़ाने से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने की है। अखिलेश ने 'एक्स' पर लिखा, कहां तो भाजपाई कह रहे थे एक देश, एक कर। लेकिन उनकी यह बात भी जुमलाई झूठ निकली, क्योंकि अब वे कर की नई 'स्लैब' ला रहे हैं। जब एक कर, कई स्लैब हैं तो एक कर का नारा सही मायनों में झूठा साबित हुआ न।उन्होंने कहा, दरअसल कर की दरें बेतहाशा बढ़ाने के पीछे एक बड़ा खेल है। यह राजस्व बढ़ाने से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने और फिर अधिकारियों के माध्यम से दुकानदारों, कारोबारियों पर दबाव बढ़ाकर ज्यादा वसूली की भाजपाई योजना है। अखिलेश ने कहा, दुनिया का नियम है कि जितनी अधिक कर की दर होती है, उतनी ही अधिक कर की चोरी होती है और जितनी अधिक कर की चोरी होती है, उतनी ही अधिक भ्रष्ट सत्ताधारियों की कमाई होती है।

फडणवीस के शपथ ग्रहण से पहले संजय राउत का तंज

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि एकनाथ शिंदे के शासन का युग खत्म हो गया है और दावा किया कि वह फिर कभी इस राज्य के सीएम नहीं बनेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर उनका इस्तेमाल करने और किनारे कर देने का आरोप लगाया. ऐसा एक दिन बाद हुआ जब भाजपा ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में शीर्ष पद के लिए देवेंद्र फड़नवीस को चुना। संजय राउत ने ने कहा शिंदे युग ख़त्म हो गया, वो सिर्फ़ दो साल के लिए था। उसका प्रयोग है। उन्होंने भाजपा पर अपनी राजनीतिक रणनीति का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं, ये तो हमेशा से बीजेपी रही है। यह सवाल करते हुए कि बहुमत होने के बावजूद महायुति गठबंधन को सरकार बनाने में 15 दिन क्यों लगे, राउत ने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर संभावित दरार का संकेत दिया और कहा कि यह मुद्दा शुक्रवार से दिखना शुरू हो जाएगा।

संसद सत्र के समय ही होती है देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश : सुधांशु

नई दिल्ली। फ्रांस के एक प्रकाशन ने हाल ही में प्रकाशित ओसीसीआरपी (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) की रिपोर्ट को लेकर एक खबर बनाई है, जिसमें दावा किया गया है कि ओसीसीआरपी की रिपोर्ट तटस्थ नहीं है और इसे अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग मिलती है। फ्रांस के अखबार की इस रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने विपक्ष को घेर लिया है और विपक्ष पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने एक खतरनाक त्रिकोण का जिक्र करते हुए राहुल को देशद्रोही तक कह डाला। दरअसल, उन्होंने एक फ्रेंच समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम आज एक खतरनाक त्रिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे मैं कह सकता हूं कि राहुल देश के सबसे बड़े गद्दार हैं।

पात्रा ने कहा, अगर सदन को छोड़कर सांसद पार्टी कार्यालय में बैठे हैं तो आप गंभीरता को समझ सकते हैं। यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश के संभुप्रता का और एकता का है। हाल ही में खुलासा हुआ कि कुछ ताकतें हैं, जो देश को तोड़ना चाहती हैं। कहीं न कहीं भारत की एकता और संभुप्रता के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं। दो दिसंबर को एक फ्रेंच अखबार ने इसका खुलासा किया है।

वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और इसे लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब भी भारत की संसद का सत्र चल रहा होता है, तभी विदेशों में कोई न कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है, जिससे देश की छवि खराब होती है। भाजपा सांसद ने भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शून्य काल के दौरान राज्यसभा में कहा कि %जब भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं, जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक, नैतिक, सामाजिक पक्ष पर हमला कर रही हैं। फ्रांस के एक प्रकाशन ने ऑर्गनाइज क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को विदेशी सरकारों की फंडिंग है और इसमें जॉर्ज सोरोस का भी कनेक्शन है। इस रिपोर्ट का फोकस भारत पर भी है।

भाजपा सांसद ने कहा कि %पिछले तीन वर्षों से ये क्या संयोग है, जब भारत की संसद का सत्र चलता है, तभी ये रिपोर्ट्स आती हैं। पूर्व में भारत के किसानों को लेकर रिपोर्ट सामने आई , तब भी संसद सत्र चल रहा था और इसी तरह पेगासस और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी लगभग उसी समय सामने आईं, जब भारत की संसद का सत्र या तो चल रहा था या शुरू होने वाला था। अब बजट सत्र शुरू होने से पहले भारत के उद्योगों के बारे में अमेरिकी अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है। क्या ये महज संयोग है या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है। विगत लोकसभा चुनाव में रूस की सरकार ने भी साफ कहा था कि भारत के चुनाव में हस्तक्षेप की कोशिश हो रही है। ये पहली बार हुआ, जब किसी सरकार ने देश के चुनाव में हस्तक्षेप की बात कही।

सुधांशु त्रिवेदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों के दिल में ये ख्वाब है कि वो भारत को झुका लेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये मत सोचें कि विदेश की किसी चीज का प्रभाव पड़ने वाला है, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विदेश का लाभ लेकर भारत में जो हो रहा है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं।

अपने वतन पर सदियों तक है, रही हुकूमत गैरों की
पर कुछ चेहरों पर अब तक है धूल उनके पैरों की।

संभल हिंसा को लेकर लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित

नईदिल्ली। संसद के दोनों सदनों में अब तक भारी हंगामा और नारेबाजी देखी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बनी हुई है। हालांकि, बीते दो दिनों से सदनों की कार्यवाही चली। लेकिन गुरुवार को संभल हिंसा को लेकर सदन में हंगामा हो गया। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को नौवा दिन था। नवें दिन लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। निशिकांत दुबे के एक बयान को लेकर विपक्ष भड़क गया। वहीं राज्यसभा में कुछ काम का जरूर हुआ। लेकिन विपक्ष का हंगामा भी समय-समय पर जारी रहा। वहीं, भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि छह हवाई अड्डों को गहन, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अदाणी समूह को पट्टे पर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को सदस्यों से नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करने और सदन में बिल्ले आदि लगाकर नहीं आने का आग्रह किया।

लोकसभा की कार्यवाही

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों पर विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर कुछ ही मिनट के अंदर दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछने के लिए कुछ सवाल उठाए जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच सदन की बैठक दोपहर करीब 12 बजकर 10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही दो बजे फिर से आरंभ होने पर कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। उनकी मांग थी कि लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई को बोलने का मौका दिया जाए। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि रेल संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा हो चुकी है और विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव को जवाब देना है, ऐसे में विपक्षी सदस्य सदन चलने दें।

पाल ने कहा, ''कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया था कि चर्चा के लिए रेल का विधेयक लेंगे। इस पर हुई चर्चा में सदस्यों ने भागीदारी की। अब माननीय मंत्री का जवाब सुनना है।'' उन्होंने गौरव गोगोई से कहा, ''शून्य प्रहर में निशिकांत दुबे जी को अवसर मिला, आपको भी अवसर मिला...आपको लगता है कि कोई विषय है तो उस पर अध्यक्ष जी को निर्णय करना है।'' संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सदन में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों का व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कहा, ''कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोगों ने हर विधेयक पर समय तय किया था। अब हंगामा कर रहे हैं...यहां तय किया गया था कि तख्तियां लेकर सदन में नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर फैशन शो किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं।'' रीजीजू ने कहा, ''इस तरह से हंगाामा करने से कुछ नहीं होगा। हंगामा करने से वोट नहीं मिलता है। चर्चा करने से लोग पसंद करेंगे।'' हंगामे के बीच ही, पाल ने रेल मंत्री वैष्णव का नाम बुधवार को हुई चर्चा परजवाब देने के लिए पुकारा। वैष्णव ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी तेज कर दी।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों में एक साल के भीतर 1.68 लाख लोगों की मौत हुई और मरने वालों में 60 प्रतिशत युवा थे। उन्होंने सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह स्थिति दुखद है और इसे रोकने के लिए समाज को भी सहयोग करना होगा।

राज्यसभा की कार्यवाही

ग्रामीण समुदायों, खास कर महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए डाक घरों को महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि इनका का आधुनिकीकरण किया गया है ताकि सेवाओं में कोई कमी न रहे और यही वजह है कि गांवों में स्वसहायता समूहों के लिए ये डाक घर निर्यात केंद्रों की भूमिका निभा रहे हैं। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेन्नासानी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि डाक घर आज भी प्रासंगिक हैं।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम किसी भी अन्य स्थान पर सबसे बड़े लोकतंत्र को गहरे राज्य द्वारा निष्क्रिय बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। इस सदन को हमारी संप्रभुता के लिए हानिकारक और खतरनाक किसी भी प्रवृत्ति, किसी भी पहल को बेअसर करने के लिए एकजुट होना चाहिए। मैं समय दूंगा। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और हमें सभी से राय लेने की जरूरत है। वहीं, सुधांशु त्रिवेदी इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओसीसीआरपी भारत में झूठी बातें फैलाता है।

गुरुवार को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2019 से 2023 तक लेटरल एंट्री मोड के जरिए विभिन्न विभागों में 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उच्च सदन में एक लिखित जवाब में बताया कि इनमें से 35 नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर और बाकी 28 अधिकारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा, %2018 से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल भर्ती की गई है, ताकि उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट असाइनमेंट के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019 में आठ संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई, जिनमें पांच अनुबंध के आधार पर और तीन अन्य सरकारी विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्त किए गए। 2021 में संयुक्त सचिव (3), निदेशक (18) और उप सचिव (9) के स्तर पर तीस भर्तियां की गईं। इनमें से 14 संविदा पर और 16 प्रतिनियुक्ति के माध्यम से थीं। वहीं 2023 में, 25 ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई, जिनमें तीन संयुक्त सचिव, 15 निदेशक और सात उप सचिव शामिल हैं। उनमें से 16 को अनुबंध के आधार पर और नौ को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किया गया है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से

एडिलेड। शुक्रवार 6 दिसंबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में डे-नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अभी तक उठने वाले सबसे बड़े सवाल कि, यशस्वी जायसवाल के साथ कौन ओपनिंग करेगा? से पर्दा उठा दिया है।

दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने पुष्टि की है कि केएल राहुल ही यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे। वहीं रोहित पिछली न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर खेली गई सीरीज के बाद से लगातार सवालों के घेरे में हैं। रोहित सीरीज की 6 पारियों में केवल एक बार पचास का आंकड़ा पार कर पाए हैं। उस दौरान वह 93 रन ही बना पाए थे। 15.16 का उनका औसत उनके टेस्ट करियर का सबसे खराब औसत रहा, जिसमें उन्होंने कम से कम तीन मैच खेले हों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में रोहित शर्मा उपस्थित नहीं थे क्योंकि वो दूसरी बार पिता बने थे जिस कारण वो भारत में ही अपने परिवार के साथ थे।

हालांकि, इसके बाद कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ भी उन्होंने ओपनिंग की। इसके बाद चर्चा हो रही थी कि क्या वह एडिलेड में ओपनिंग करेंगे? रोहित शर्मा ने जानकारी दी है कि ऐसा ही होगा।

रोहित ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और जायसवाल के साथ उनकी साझेदारी ने उस पहले टेस्ट की जीत में अहम भूमिका निभाई। जिस तरह से उन्होंने भारत के बाहर बल्लेबाजी की है वह इसके हकदार हैं। मैं बीच में कहीं बल्लेबाजी करूंगा। ये काफी सरल निर्णय था। व्यक्तिगत रूप से बल्लेबाज के तौर पर ये आसान नहीं था, लेकिन टीम के लिए ये एक आसान निर्णय था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में रौनक सेंसेक्स 809 अंक बढ़ा

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत रुझानों और विदेशी फंड फ्लो के बीच चौतरफा खरीदारी से गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा। आईटी कंपनियों के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखी गई। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1 प्रतिशत बढ़ा। 30 शेयरों वाला, बीएसई सेंसेक्स आज 226.41 अंक की बढ़त पर खुला। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 82,317.74 की ऊंचाई पर पहुंच गया था। दिन के दौरान यह इंडेक्स 80,467.37 के निचला स्तर पर भी आया। हालांकि कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 809.53 अंक या 1.00 प्रतिशत की शानदार बढ़त लेकर 81,765.86 बंद हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 240.95 अंक या 0.98 प्रतिशत मजबूत होकर 24,708.40 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,295.55 और 24,857.75 के रेंज में कारोबार हुआ।

नई एमएफ स्कीम से भविष्य सुरक्षित बनाने में करेगी मदद

नईदिल्ली। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड ने इक्विटी कैटेगरी में नया फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च किया है। म्युचुअल फंड हाउस की नई स्कीम बड़ौदा बीएनपी पारिबा चिल्ड्रेन्स फंड एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड टारगेट आधारित स्कीम है। इसे बच्चों के बेहतर भविष्य या बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने में माता-पिता की मदद करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। यह एनएफओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 6 दिसंबर 2024 को खुल रहा है और 20 दिसंबर 2024 को बंद होगा। बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड की इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई है। इसके फंड मैनेजर प्रतीश कृष्णन हैं। इस स्कीम में एकमुश्त और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दोनों तरीकों से निवेश किया जा सकता है।

1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी ह्युंडै की कारें

नईदिल्ली। देश की दिग्गज कार मैन्युफैक्चरर ह्युंडै मोटर इंडिया लिमिटेड की कारें खरीदना नए साल में महंगा हो जाएगा। हुंडई मोटर ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि 1 जनवरी 2025 से कंपनी के सभी मॉडल की कीमतें बढ़ जाएंगी। कंपनी ने बताया कि इनपुट कॉस्ट में इजाफा, एक्सचेंज रेट का असर और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते कंपनी ने दाम बढ़ाने का फैसला किया है। ह्युंडै मोटर इंडिया के होल-टाइम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी ने हमेशा बढ़ती का असर कस्टमर्स पर न पड़े या कम से कम असर हो, इसकी कोशिश की है। हालांकि, अब इनपुट कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी के चलते मामूली इसका कुछ असर कस्टमर्स पर डालना जरूरी हो गया है। ह्युंडै की यह बढ़ोतरी सभी मॉडल पर लागू होंगी और कीमतों में 25,000 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। यह बदलाव सभी मार्केटिंग ईयर 2025 मॉडल्स पर लागू होगा।

बजाज फिनसर्व एएमसी के एनएफओ में निवेश का मौका!

नईदिल्ली। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बजाज फिनसर्व एएमसी ने इक्विटी कैटेगरी में नया सेक्टोरल फंड बजाज फिनसर्व हेल्थकेयर फंड ला रहा है। फार्मा थीम पर यह न्यू फंड ऑफर 6 दिसंबर से सब्सक्रिप्शन खुल जाएगा और 20 दिसंबर 2024 को बंद होगा। इस स्कीम का निवेश फार्मास्युटिकल और हेल्थकेयर से जुड़ी कंपनियों में करने पर फोकस है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बजाज फिनसर्व का कहना है कि इस स्कीम में न्यूनतम 500 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ 100 रुपये व उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में अतिरिक्त आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में अलॉटमेंट की तारीख से 3 महीने के भीतर रिडम्पशन पर 1 फीसदी एग्जिट लोड देना होगा। फंड के इक्विटी हिस्से का मैनेजमेंट निमेश चंदन और सौरभ गुप्ता संयुक्त रूप से करेंगे। जबकि डेट हिस्से का प्रबंधन सिद्धार्थ करेंगे।

अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निजी निवेश जरूरी

अभिजीत मुखोपाध्याय

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में आर्थिक विकास दर जब 6.7 प्रतिशत आंकी गयी, तब अनेक विशेषज्ञों ने कहा था कि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपनी विकास दर मजबूत है। यह भी कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के कारण सरकारी और निजी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां रुक गयी थीं, इसलिए केंद्र में नयी सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन और बेहतर होगा। परंतु जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में विकास दर घटकर 5.4 फीसदी रह गयी। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर मात्र 2.2 फीसदी और खनन क्षेत्र में तो नकारात्मक यानी 0.1 प्रतिशत रही। जबकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर 8.1 प्रतिशत थी।

बेहतर मानसून के बावजूद अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की- जिनमें कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां प्रमुख हैं- विकास दर मात्र तीन प्रतिशत रही। सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्र में बिजली, गैस और दूसरी सार्वजनिक जरूरतों के क्षेत्र में आर्थिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के 10.5 प्रतिशत से घट कर इस साल महज 3.3 फीसदी रह गयी। जबकि टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण के क्षेत्र में भी विकास दर में गिरावट आयी। अलबत्ता वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में विकास दर तुलनात्मक रूप से बेहतर 6.7 प्रतिशत रहीं। हालांकि लोक प्रशासन, रक्षा और दूसरी सेवाओं में आर्थिक दर पिछले साल की इसी अवधि की 7.7 फीसदी की तुलना में कहीं ज्यादा 9.2 प्रतिशत रही। सीधे शब्दों में कहें, तो पूंजीगत

खर्च के क्षेत्र में सरकार का निवेश जारी है, और इसी कारण विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आयी गिरावट के बावजूद कमोबेश भरपाई हो जा रही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतिम उपभोग खर्च, यानी जीएफसीइ में 4.4 प्रतिशत की विकास दर से भी स्पष्ट है।

अच्छी बात यह है कि निजी क्षेत्र में अंतिम उपभोग खर्च, यानी पीएफसीइ की विकास दर अपेक्षाकृत बेहतर छह फीसदी रही। हालांकि निवेश के मोर्चे पर पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि की तुलना में प्रदर्शन फीका रहा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉरमेशन (जीएफसीएफ) या निवेश की विकास दर 5.4 प्रतिशत रही। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 10.2 फीसदी थी।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि उपभोग की मांग में कमोबेश वृद्धि हो रही है, पर उम्मीदों के अनुरूप निजी निवेश रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने के कारण अप्रैल से सितंबर तक पूंजीगत खर्च में भी 15.4 फीसदी की कमी देखी गयी। एक हालिया अध्ययन बताता है कि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने के बजटीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूंजीगत खर्च में 52.04 फीसदी की तेज वृद्धि करनी होगी, जो मुश्किल लगती है। दूसरी तिमाही की आर्थिक विकास दर को स्तब्ध करने वाला बताया जा रहा है, लेकिन यह कमोबेश प्रत्याशित ही थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में बताती है। कम पूंजीगत खर्च, निजी क्षेत्र के निवेश में कमी और उपभोग के सामान्य रहने से अर्थव्यवस्था के असली चेहरे को सामने आना ही था। यह उम्मीद करनी चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन, बिक्री और राजस्व के मोर्चे पर अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर हो। लेकिन अब लगता यही है कि मौजूदा वित्त वर्ष की आर्थिक विकास दर छह फीसदी से नीचे चली जायेगी।

संभावना यह भी है कि वित्त वर्ष की आखिरी छमाही में अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी, पर यह भी सच है कि मौजूदा आर्थिक चुनौतियां बरकरार रहेंगी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष की आर्थिक विकास दर पहले 7.2 फीसदी आंकी थी। लेकिन मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक में वह विकास दर का अपना आकलन बदलेगा। नवंबर की बुलेटिन में देश के केंद्रीय बैंक ने दूसरी तिमाही की विकास दर 6.7 फीसदी तथा तीसरी तिमाही में 7.6 प्रतिशत आंका था।

तुहँर हाथ तुहँर टोकन एप के माध्यम से किसानों ने लगभग 45 हजार टोकन स्वयं काट लिए हैं - संदीप शर्मा

साय सरकार में धान खरीदी तेज रफ्तार से चल रही है - संदीप

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा धान खरीदी केंद्रों पर औचक निरीक्षण को महज सियासी ड्रामेबाजी बताया है। श्री शर्मा ने कहा है कि इस कथित निरीक्षण के नाम पर प्रदेशभर में सुव्यवस्थित रीति से चल रही धान खरीदी की प्रक्रिया में खलल पैदा करना और धान खरीदी को लेकर झूठे तथ्यों के साथ प्रदेश के किसानों को गुमराह करके उन्हें उकसाना और फिर अव्यवस्था व अराजकता फैलाना ही कांग्रेस नेताओं का एजेंडा है। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के नेतृत्व में इस वर्ष धान खरीदी तेज रफ्तार से चल रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि दरअसल कांग्रेस को यह हजम ही नहीं हो रहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार बिना किसी अवरोध और अप्रिय प्रसंग के सुव्यवस्थित रीति से प्रदेश के किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है और समर्थन मूल्य तथा अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि बारदाना और टोकन को लेकर कांग्रेस ने लगातार झूठ फैलाकर किसानों को उकसाने की नाकाम कोशिशें करके मुँह की खाई है।

आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने बारदाना संकट का सौहार्द्रपूर्ण समाधान किया है, जबकि कांग्रेस की भूपेश सरकार हर साल बारदाना के नाम पर केंद्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ने में लगी रहती थी। इसी प्रकार तुहँर हाथ तुहँर टोकन एप के जरिए किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि वह स्वयं अपना टोकन स्वयं काट सकें और इस ऐप के माध्यम से किसानों ने लगभग 45 हजार टोकन स्वयं काट लिए हैं। आगे की धान खरीदी के लिए लगभग एक लाख से ज्यादा टोकन जारी किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों का पूरा धान नहीं खरीदने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के दरअसल अपना गिरेबाँ झाँक लेना चाहिए जब उसके शासनकाल में किसानों का धान खरीदने से बचने के लिए गिरदावरी आदि तमाम छल-प्रपंचों का सहारा भूपेश सरकार लेती थी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि पिछले साल के 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के विरुद्ध इस वर्ष प्रदेश की भाजपा सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से 30 लाख टन अधिक है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 27.60 लाख (पिछले साल की तुलना में डेढ़ लाख से अधिक) किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और रकबा के हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस वर्ष किसानों ने लगभग 3.80 लाख एकड़ अधिक भूमि का पंजीयन कराया है। 14 नवंबर से अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं, 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 5,994 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। श्री शर्मा ने कहा कि जिस तेज रफ्तार और प्रणाली से धान खरीदी की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है, उससे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निर्धारित अवधि तक प्रदेश सरकार धान खरीदी का अपना लक्ष्य अर्जित करेगी। धान खरीदी में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना किसानों को नहीं करना पड़ रहा है। प्रदेश के किसान साय-सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था को भूरि-भूरि प्रशंसा कर धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किया था, उसको निभाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा और किसान भाजपा सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों का धान खपाने कोचिए सक्रिय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों पर है. किसान अपने धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के धान को खपाने के लिए कोचिए सक्रिय हो चुके हैं. दरअसल, छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और प्रति क्विंटल 3100 की दर से खरीदी की जा रही है. ऐसे में दूसरे राज्यों के धान को खपाने की कोशिश जारी है. इसपर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है. अब तक प्रदेश में 33 हज़ार 54 क्विंटल धान जब्त कर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है. साथ ही 86 गाड़ियों को अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया है. बता दें कि प्रदेशभर में धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए 273 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं. जहां चेक पोस्टों पर खाद्य, राजस्व, मंडी, कृषि विभाग की अधिकारी की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है.

पीएम-सीएम प्रत्यक्ष चुना जा सकता है तो निकायों में क्यों नहीं?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ओबीसी सर्वे में गड़बड़ी का संदेह जताते हुए कहा कि सर्वे में ओबीसी की आबादी कम बताई गई है. सरगुजा में ओबीसी सर्वे में अनारक्षित वर्ग के लोगों ने अपना नाम जुड़वाया है.

ऐसे में कई इलाकों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा. वहीं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेता अजय चंद्राकर के बयान पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यदि

इनडायरेक्ट चुना जा सकता है तो निकायों में क्यों नहीं? सिंहदेव ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग नीचे हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं, ये कैसा तर्क है. इसमें वन नेशन वन प्रक्रिया क्यों नहीं करते. दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि प्रणाली बदलती रही है. आजकल ऑपरेशन लोटस चलन में है. नियम कानून आए, लेकिन रुक नहीं रहा है. सभी असफल रहा. जीतने कड़े कानून बना सके बनाना चाहिए. यदि कोई दल बदलता है तो आगे कुछ समय तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देना चाहिए.

एकलव्य विद्यालय मामले में केदार कश्यप के बयान को बताया शर्मनाक

नारायणपुर के एकलव्य विद्यालय के वायरल वीडियो को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने शर्मनाक बताया है. वन मंत्री केदार कश्यप के वीडियो बनाने वाले पर कार्रवाई करने के बयान पर सिंहदेव ने कहा, यदि व्यवस्था ऐसी है तो अमानवीय है. इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.

'शिक्षा–स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं हुई कोई प्रगति'

बीजेपी के जनादेश दिवस को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह ने कहा है कि काम नहीं के बराबर हुआ है. एक महतारी योजना ही लागू किया. बिजली से लोग परेशान हैं. शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई प्रगति नजर नहीं आ रहा है. कई क्षेत्रों में स्थिति और खराब हुई है.

बलरामप्रसाद वर्मा रायपुर के नये जिला एवं सत्र न्यायाधीश

थोक के भाव में हुए न्यायाधीशों के तबादले

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुधवार की देर शाम को जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के पदोन्नति और उनके पदस्थापना आदेश जारी किए गए है। रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी अब बलौदाबाजार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे, उनके रिक्त हुए स्थान पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ बलराम प्रसाद वर्मा रायपुर के नये जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे। यह स्थानांतरण न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा के पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

जज कंवरलाल चारयानी वर्तमान में धमतरी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, अब सरगुजा (अंबिकापुर) में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए गए हैं। रामकुमार तिवारी वर्तमान में सरगुजा (अंबिकापुर) के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अब धमतरी में इसी पद पर नियुक्त किए गए हैं। हेमंत सराफ वर्तमान में रायपुर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, अब बलरामपुर-रामानुजगंज में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए। अब्दुल जाहिद कुरैशी वर्तमान में रायपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अब बलौदाबाजार में इसी पद पर स्थानांतरित किए गए हैं। उच्च न्यायालय में के. विनोद कुजर रजिस्ट्रार (उच्च सेवा न्यायिक) के पद पर कार्यरत हैं जिन्हें अब रजिस्ट्रार जनरल (स्थापना) के रूप में नियुक्त किया गया है। खिलावन राम रिगरी विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) से रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पद पर स्थानांतरित किए गए हैं। अगम कुमार कश्यप, रायपुर में नौवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश से अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पद पर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए गए हैं। संतोष ठाकुर, रायगढ़ में छठे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पद से अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) के पद पर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए गए हैं। अशोक कुमार साहू, बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायपुर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश बिहारी घोरे, बलौदाबाजार-भाटापारा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जशपुर परिवार न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। गीता नेवारे, जशपुर परिवार न्यायालय की न्यायाधीश को जांजगीर-चांपा परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजेंद्र कुमार वर्मा, जांजगीर-चांपा परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा बनाया गया है। विवेक कुमार तिवारी (वरिष्ठ), जांजगीर-चांपा में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश को रायपुर परिवार न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। दीपक कुमार देशलहरे का दंतेवाड़ा के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद से स्थानांतरण करते हुए उन्हें कानून एवं विधायी कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। उन्हें अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार के रूप में अटल नगर, नवा रायपुर में पदभार ग्रहण करना होगा।

भाजपा सरकार एक साल में विफल साबित हो गयी: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो गई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर विष्णु की सरकार कही नहीं दिख रही। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गयी आरंग में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो गयी। राजधानी में 5 बार गोलीबारी हो गयी। गौ तस्करी की घटनाएं शुरू हो गयी। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गयी, पोटाकेबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी हो गयी। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनायें बढ़ गयी। लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी की घटनायें बढ़ गयी। अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके है। नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो गयी। नक्सली घटनायें बढ़ गयी सरकार ने 1 साल में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्यायें कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है।

रेत के दाम तीन गुना बढ़ गये। भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच सांठगांठ हो गयी है, रेत के कारोबार में रोज खून बहाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया है। जनकल्याणकारी योजनाएं बंद हो गयी है। सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण 1 साल में ही राज्य के खजाने पर 37000 करोड़ से अधिक का कर्जा हो गया है। युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। सरकारी नौकरी में भर्तियां बद हो गयी। बिजली के दाम बढ़ गये। एक साल में ही साय सरकार जनता में अलोकप्रिय साबित हो गयी है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख आवास देने का वादा था, 1 साल में 1 भी नया मकान नहीं दे पाये। कांग्रेस राज में 7 किलो राशन मिलता था उसमें कटौती हो गयी। सरप्लस बिजली वाले छत्तीसग? में बिजली कटौती शुरू हो गयी। जमीनों की रजिस्ट्री में जनता को लूटा जा रहा है। भूमि के गाईड लाईन के दर में 30 प्रतिशत के छूट को समाप्त कर दिया। लेकिन रजिस्ट्री फीस में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को नहीं हटाया गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं, डॉक्टर मुर्गा पार्टी कर रहे

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही, डॉक्टर मुर्गा पार्टी कर रहे। दुर्ग जिला के कन्हारपुरी सरकारी अस्पताल जिसे 10 बजे खुलने के बाद 4 बजे बंद होना था। लेकिन अस्पताल को 2 बजे ही बंद कर वहां मुर्गा पार्टी किया जा रहा था। और यह कोई पहली घटना नहीं है इसके पहले भी दुर्ग जिला के कई सरकारी अस्पतालों में दारू पार्टी, मुर्गा पार्टी की खबरें सामने आई है, उसके बावजूद सरकार इसे सुधारने की दिशा में कोई काम नही किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मीडिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बताने बड़े-बड़े दावे करते हैं लेकिन हकीकत में स्थिति यह है कि सरकारी अस्पताल सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है अस्पतालों में समय पर चिकित्सक नही मिलते दवाईयां टेस्टिंग किट की कमी है, एक्सरे, सीटी स्किन, एमआरआई, नही हो रहा है ऑक्सीजन, बेड की कमी है। मरीज ईलाज के लिए भटक रहे आयुष्मान योजना में निजी अस्पताल ईलाज नही कर रहे है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से स्वास्थ्य व्यवस्था संभल नहीं रही है.

महंगाई से जनता बदहाल हो गयी - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही महंगाई बेलगाम हो चुकी हैं। 1 डॉलर की कीमत 84 रुपये 68 पैसे तक पहुंच गया है। विगत 10 वर्षों में क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग आधा है, फिर भी कीमतों में कटौती का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। 2014 की तुलना में आधी कीमत पर क्रूड ऑयल खरीद कर केंद्र की मोदी सरकार आम जनता से डीजल, पेट्रोल का डेढ़ गुना दाम वसूल रही है। रसोई गैस की कीमतें तीन गुना अधिक वसूली जा रही है। दूध, दही, पनीर, आटा, मैदा, सूजी, दलहन तिलहन, कपड़े जैसे दैनिक उपभोग की तमाम वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाकर महंगी कर दी गई है, दवाओं और अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार जनता की जेब में खुलेआम डकैती कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मोदी राज में महंगाई बेलगाम आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। जन विरोधी मोदी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क में 22 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि की, जिसके चलते ही बाजार में सभी तरह के खाद्य तेलों के दाम लगभग डेढ़ गुना बढ़ गए।

स्कूल के समीप तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

बिलासपुर/रायपुर। हाई कोर्ट में बिलासपुर के स्कूलों के आस-पास और अन्य सार्वजनिक जगहों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर संज्ञान में लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ के सामने मुख्य सचिव और बिलासपुर निगम आयुक्त ने हलफनामा पेश किया. मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2025 को होगी. दरअसल, मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 नवंबर 2024 को छुट्टी के दिन हाई कोर्ट की बैठक हुई. मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया. इसके बाद लगातार सुनवाई जारी है. महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने आज सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र में जानकारी दी कि आदेश का परिपालन करते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पेनल्टी और अन्य कार्रवाई की है. वहीं गंभीरता से कोटपा कानून का पालन कराया जा रहा है. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को निर्देश देते हुए सतत् निगरानी करने कहा है. वहीं कोटपा कानून 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में बिलासपुर निगम आयुक्त को अपना व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को रखी गई है.

दर्जनों गायों की मौत के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार

रायपुर। दुर्ग जिले में दर्जनों गायों की भूख प्यास से मौत पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि गोढ़ी गौठान का वीभत्स मंजर साय सरकार के कुशासन का प्रमाण है, गोढ़ी गोठान में आज भी अनेकों गौ माता के अंग चारों तरफ बिखरे पड़े है। कुछ मृत गौवंशी पशुओं को गोठान के बाहर फेक दिया गया है। चारा-पानी के अभाव में कई गायें तड़प रही है। गाय के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपाईयों और प्रशासन के जिम्मेदारों को आज तक सुध लेने की फुर्सत नहीं है।

भाजपा सरकार की दुर्भावनापूर्ण नीतियों के चलते गौवंशी पशु बदहाल हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित साय सरकार ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हजारों की संख्या में गौठानो को बंद कर दिया। गौ अभ्यारण्य केवल कागज़ी जुमला निकला। विगत 1 वर्ष के दौरान सैकड़ो गायें सड़कों पर दुर्घटना का शिकार होकर मारी गई। किसान खुली चराई से परेशान है, और गौ माता चारा-पानी और इलाज के अभाव में बे-मौत मारी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि गोढ़ी गौठान में हुई गायों की मौत के लिये भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

भूख-प्यास से 10 से ज्यादा गायों की मौत

दुर्ग./रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गौठानों की बदहाल स्थिति का शिकार बेजुबान जानवर हो रहे हैं. जिले के नंदनी थाना क्षेत्र के गोढ़ी गांव के गौठान में इस तरह भयावह दृश्य देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई सहम उठेगा.

यहां के गौठान में 10 से ज्यादा गायों की भूख-प्यास से मौत हो गई. यहां चारा-पानी की व्यवस्था किए बगैर गायों को रखा जा रहा है. छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय में बनाया गया गोठान भाजपा सरकार में बंद हो गया. यहां बनी कमेटी भी भंग कर दी गई है. इससे मवेशी खुले में घूम रहे हैं. कुछ किसानों ने यहां के सरपंच गोपी साहू से उनकी फसल चरने की चिंता जताई. सरपंच गोपी साहू पर ग्रामीणों का आरोप है कि उसने किसानों की फसल को बचाने के लिए स्वयं एक कमेटी बनाई. इसके बाद मवेशियों को गौठान में बांध दिया. वहां चारा-पानी ना मिलने से 10 मवेशियों की भूख-प्यास से मौत हो गई. गांव के पंच पति डोमार सिंह ने गायों की मौत के लिए सरपंच गोपी साहू को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि किसानों की फसल को चरने से बचाने के लिए सरपंच ने एक कमेटी बनाई.

मिट्टी स्वस्थ होगी तभी हमारी सेहत अच्छी रहेगी: डॉ. चंदेल

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा है कि मिट्टी हमारी कृषि, भोजन और जलवायु संतुलन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसल तैयार होती है और स्वस्थ फसल से मनुष्यों का स्वास्थ अच्छा रहता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में मिट्टी के घटते स्वास्थय के कारण पर्यावरण असंतुलन, जैव विविधता में कमी और कृषि उत्पादकता में गिरावट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मिट्टी की देखभाल तथा उचित प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने खेतों में जीवांश पदार्थों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया। डॉ. चंदेल

आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, रायपुर द्वारा आयोजित विश्व मृदा दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कुलपति डॉ. चंदेल द्वारा किसानों को जवाहर नवोदय विद्यालय, माना एवं केन्द्रीय विद्यालय, रायपुर के छात्रों द्वारा तैयार उनके खेतों के मृदा स्वास्थय कार्ड भी प्रदान किये गये।

इस अवसर पर ''मिट्टी की देखभाल - मापन, निगरानी तथा प्रबंधन'' विषय पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसमें मृदा वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को मिट्टी की समुचित देखभाल तथा मृदा ऊर्वरता प्रबंधन पर जानकारी दी गई।

संगोष्ठी में बताया गया कि कृषि में मिट्टी के महत्व तथा उसकी गुणवत्ता में आ रही खराबी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2013 से 5 दिसम्बर के दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत की 30 प्रतिशत मिट्टी प्रदूषण एवं उर्वरता की कमी से प्रभावित है। पिछले दो दशकों में मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर 23 प्रतिशत तक घटा है, और 40 प्रतिशत कृषि भूमि में पोषक तत्वों की गंभीर कमी देखी गई है। बताया गया कि वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब होने का अनुमान है। जिससे खाद्यान की मांग 330 मिलियन टन से ब?कर 350 मिलियन टन हो जाएगी। इस मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी के स्वास्थ और मृदा ऊर्वरता को बनाये रखना आवश्यक है। संगोष्ठी में वैज्ञानिकों द्वारा खेतों में जीवांश कार्बन का अधिक उपयोग, ऊर्वरकों का संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती तथा फसल चक्र परिवर्तन की सलाह दी गई।

राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करें: अजय सिंह

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग,नगरीय प्रशासनएवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारिओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव श्री तारण सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और

निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। मतदान दलों के मानदेय एवं उनके परिवहन हेतु वाहनों के किराये के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.